

नई दिल्ली
गुरुवार
15 अक्टूबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 41
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail story@sadbhawna.today sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

नाव दुर्घटना पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा मिले,...**पेज-05**

DELHIN/2014/58158

प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे और एयर थो की...पेज-08



एक नजर

सीजेपी नेता दीपके की 16 अक्टूबर को सीपी के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने की अपील

नई दिल्ली। कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने लोगों से 16 अक्टूबर को कर्नाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम को इकट्ठा होने और साथ में तिरंगा लाने की अपील की है। उनका यह बयान सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के बाद आया है। सीजेपी का आरोप है कि दोनों को जंतर मंतर में तिरंगा लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दीपके आज सुबह दिल्ली पहुंचे और शाम को उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से यह अपील की। उन्होंने कहा कि उनके साथियों को तिरंगा लहराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हम सबको तिरंगा लेकर वहां पहुंचना चाहिए और सरकार को यह दिखाना चाहिए कि तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सीजेपी नेताओं को कल जंतर-मंतर से हिरासत में लिया गया था। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जमानत अनुबंध का अनुपालन नहीं करते हुए गैर-अधिसूचित जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रदर्शन करने की कोशिश की।

थोक महंगाई दर सितंबर महीने में बढ़कर रिकॉर्ड 11.39 फीसदी पर पहुंची



नई दिल्ली.हि.स। महंगाई के गोचर पर आम आदमी को झटका लगाने वाली खबर है। खुदरा महंगाई दर के बाद खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन एवं बिजली की कीमतों में तेज उछाल से सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 फीसदी पर पहुंच गई है, जो अगस्त में 9.92 फीसदी थी। यह पांच महीने का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक महंगाई दर के जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी है। आकड़ों अनुसार खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अगस्त के 7.05 फीसदी से बढ़कर सितंबर में 8.66 फीसदी ले गई। विनिर्मित वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर भी बढ़कर 9.76 फीसदी के श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अगस्त में यह 8.37 फीसदी थी। ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर सितंबर में 25.85 फीसदी रही, जबकि पिछले महीने अगस्त में यह 22.93 फीसदी रही थी। मंत्रालय ने डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, कोयले एवं लिग्नाइट, बुनियादी धातुओं, रसायनों एवं रासायनिक उत्पादों, वस्त्रों, रखर एवं प्लास्टिक उत्पादों तथा बिजली के उपकरणों की कीमतों में बहोतरी से सितंबर में थोक महंगाई की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने पिछले हफ्ते ही नीतिगत दर रेपो रेटे में 0.25 फीसदी की बहोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। वहीं, इस सप्ताह की थुरुआत में जारी खुदरा महंगाई दर भी खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बहोतरी के कारण सितंबर में बढ़कर 23 महीने के उच्च स्तर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई।

मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पर दिल्ली कैबिनेट ने पारित किया अभिनंदन प्रस्ताव

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली कैबिनेट ने सर्वसम्मति से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति ढाई करोड़ दिल्लीवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फरवरी 2025 में दिल्ली में सरकार बनने के बाद केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और राजधानी के विकास को गति देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं और वित्तीय एवं तकनीकी

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना हुडे

आवाज़ अधिकार की

रेलवे के 11.4 लाख कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी



नई दिल्ली,एजेंसी। सरकार ने रेलवे के 11.4 लाख कर्मचारियों के लिए बुधवार को 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि रेलवे के 11,40,770 अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के पात्र हैं। इसके लिए 2,009.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए 78 दिन का अधिकतम बोनस 17,951 रुपये होगा। रेलवे कर्मचारियों में ट्रेक

मेनटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (पहले गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, प्वाइंट्समैन, मंत्रालय के कर्मचारी और ग्रुप सी के अन्य कर्मचारी बोनस के पात्र होते हैं। यह बोनस हर साल दिया जाता है। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में इस समय 1.65 लाख विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमें पिछले कुछ समय में 37 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि साल 2014 से अबतक रेलवे में 5.5 लाख भर्ती की गई है। रेलवे के मौजूदा कर्मचारियों में करीब आधे ऐसे हैं जिनकी भर्ती साल 2014 के बाद हुई है।

पुलिस हिरासत में छात्रों से मारपीट के आरोप, राहुल ने पेश किए प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया है। राहुल ने बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्होंने पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए।

राहुल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपने साथ हुई घटनाओं के वीडियो और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राहुल गांधी ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्र, युवा और अन्य लोग अलग-अलग समुदाय और वर्गों से आते हैं, लेकिन उनकी आवाज एक है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की आवाज के



खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सभी साक्ष्यों का इस्तेमाल कर मारपीट के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की जाएगी। केरल की छात्रा अथिरा ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान बस में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बारे में पूछने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि कर्नाट प्लेस थाने के सामने उल्टे पीटा गया, जिससे उनकी आंख और कान में चोट आई। अथिरा के अनुसार, उनके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है। बांसुरी वादक समर ने भी हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया।

नशे के मुद्दे पर भाजपा का पंजाब की आआपा सरकार पर हमला, मान का मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली। पंजाब में नशे की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा की पंजाब प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य में नशे, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मीयों की कथित सत्तिसत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है और आदर्श आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रही है। ढिल्लों ने भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पंजाब गुरुओं, पोरों और पैगंबरों की धरती रही है। हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले इस राज्य का, आज नशे की गिरफ्त में फंसना बेहद चिंताजनक है। भाजपा ने पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में नशा विरोधी यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा को चार दिशाओं से शुरू किया गया और जालंधर में इसका समापन हुआ।

सौरव दास और आशुतोष रांका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो नेताओं को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत 14 सदस्यों के खिलाफ कर्नाट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अलग-अलग दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सीजेपी के ये सदस्य प्रतिबंधित जंतर-मंतर पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे और पुलिसकर्मीयों के काम में बाधा डाली। इसके बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में लिया था। तीनों को आज सुबह स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे को छह



महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5,000 रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। इसका मतलब है कि जंतर-मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसी फैसले के विरोध में सीजेपी के नेताओं ने ये प्रदर्शन किया था। नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा के अनुसार, यह घटना

पीएम मोदी आज लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपये की पांच विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर, गुरुवार को लद्दाख में करीब 3,350 करोड़ रुपये की पांच विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में हवाई संपर्क, सामरिक सड़क कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे के 640 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 23,800 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल सालाना 35 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग किया गया है। आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को समाहित करने वाला यह टर्मिनल क्षेत्र का हवाई संपर्क बेहतर करेगा। प्रधानमंत्री 298 किलोमीटर लंबी निम्न-पदुम-दरचा सड़क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सीमा सड़क संभटन (बीआरओ) द्वारा निर्मित यह सड़क लेह के निम्नू को हिमाचल प्रदेश के दरचा से जोड़ती है और दूरस्थ जांस्कर घाटी से होकर गुजरती है। यह श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह राजमार्गों के अतिरिक्त लद्दाख के लिए वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगी। ऊंचाई वाले शिंकुन ला दर सहित दुर्गम हिमालयी क्षेत्र से गुजरने वाली इस सड़क से सशस्त्र बलों की आवाजाही और रसद आपूर्ति को



मजबूती मिलेगी। साथ ही, स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र की जलविद्युत क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नौ मेगावाट की हानू लघु जलविद्युत परियोजना तथा 66 केंवी की डबल-सर्किट दाह-हानू-खाल्त्सी परेपण लाइन का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उत्पादित बिजली के परेपण की व्यवस्था मजबूत होगी। लद्दाख की प्राचीन पुरातात्विक विरासत के संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और उत्कीर्ण आकृतियों के सैकड़ों स्थल हैं, जिनमें वन्यजीवों, मानव आकृतियों और प्रतीकात्मक चित्रों के माध्यम से हजारों वर्षों के इतिहास की झलक मिलती है। यह पार्क इन दुर्लभ पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण, जन-जागरूकता और जिम्मेदार विरासत पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

बिहार: वैशाली जिले के राघोपुर में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत



थे। नदी की बीच धारा में अचानक नाव पलटने से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते लोग गहरे पानी में गिरने लगे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी दी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और अपने स्तर से लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री सप्रता चौधरी ने भी नाव हादसे पर दुःख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद खबर प्राप्त हुई। डूबने वालों में से अधिकांश बच्चे हैं। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। उन्होंने स्थानीय लोगों व प्रशासन से वार्ता कर राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा ह।

आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा- राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद खबर प्राप्त हुई। डूबने वालों में से अधिकांश बच्चे हैं। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। उन्होंने स्थानीय लोगों व प्रशासन से वार्ता कर राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा ह।

मामले में पहली प्राथमिकी कर्नाट प्लेस थाने में एफआईआर संख्या 289/26 के तहत दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए), 332 और 61(2) लगाई गई हैं। दूसरी प्राथमिकी संसद मार्ग थाने में एफआईआर संख्या 128/26 के तहत दर्ज हुई है। इसमें बीएनएस की धारा 221, 115(2), 132, 121(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में कुल 14 सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सीजेपी के प्रमुख सदस्यों आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे के खिलाफ अलग से निवारक कार्रवाई की। पुलिस का आरोप है कि इन सदस्यों की गतिविधियों से सार्वजनिक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि तीनों इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी इसी तरह की गतिविधियों के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे थे।

मुखर्जी नगर में विद्यार्थियों के बीच पहुंचीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार देर शाम राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक एवं कोचिंग हब मुखर्जी नगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चाय की दुकान पर विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और पढ़ाई, आवास, महिला सुरक्षा तथा बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। विद्यार्थियों ने निःशुल्क लाइब्रेरी की कमी, पीजी के अधिक किराए, जमानत राशि, दलाली, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति जैसे मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने आए युवा राजधानी के परिवार का हिस्सा हैं। उनकी सुविधाओं, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

विद्यार्थियों ने क्षेत्र में किफायती लाइब्रेरी की कमी और मौजूदा लाइब्रेरी के बार-बार बंद होने से पढ़ाई प्रभावित होने की समस्या बताई। इस पर



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लाइब्रेरी की स्थिति, भवन संबंधी कमियां और सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय विधायक और अधिकारियों से खाली प्लॉट तथा उपलब्ध सामुदायिक भवनों में उपयुक्त स्थान चिह्नित करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी विकसित की जा सके। विद्यार्थियों ने पीजी के अधिक किराए, जमानत राशि और दलाली के कारण होने वाले खर्च की समस्या भी उठाई। उन्होंने बताया कि पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध नहीं होने के

कारण उन्हें निजी पीजी या किराये के कमरों में रहना पड़ता है। छोटे कमरों, सीमित वेंटिलेशन, भोजन की गुणवत्ता और आसपास चलने वाले निर्माण कार्यों से भी उन्हें परेशानी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीजी पॉलिसी और नए हॉस्टलों की उपलब्धता जैसे विषयों पर काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें बेहतर और व्यवस्थित आवास सुविधाएं मिल सकें। छात्राओं ने देर शाम आवागमन के दौरान सुरक्षा

संबंधी कठिनाइयों और कुछ स्थानों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस प्रतिनिधियों को स्ट्रीट लाइट तथा सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। नियमों के विरुद्ध गहरे रंग की फिल्म लगे वाहनों के आवागमन की शिकायत पर भी उन्होंने पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय को पिक टॉयलेट के रूप में विकसित कर जल्द चालू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने को भी कहा। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले विद्यार्थियों ने गलियों में गंदगी, कूड़े और दुर्गंध की समस्या उठाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और मुख्य सड़कों के साथ छोटी गलियों तथा आवासीय क्षेत्रों में भी सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों ने बारिश के दौरान सीवर का पानी पेयजल आपूर्ति में मिलने की आशंका और पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जांच करने और पेयजल की गुणवत्ता का आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।

दिल्ली एसआईआर मामले में अब 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एसआईआर मामले में सुनवाई की तारीख बदल दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर के बजाय 28 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाम कटने वाले वोटरों से दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग से नियम स्पष्ट करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं अर्जल भारद्वाज और अमृता जोहरी की की ओर से पेश वरिष्ठवकील प्रतिष्ठत भूषण ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिल्ली में करीब 47 लाख से अधिक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रशंति भूषण ने कहा कि अब निर्वाचन आयोग इन हटाए गए

वोटरों से नाम दोबारा जुड़वाने के लिए ‘फॉर्म-6’ भरने को कह रहा है। फॉर्म-6 में यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक ‘पहली बार’ वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि जो लोग पहले से ही वोटर थे, वे यह झूठी घोषणा कि नाम कटने वाले वोटरों से दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग नियमों को स्पष्ट करे और हटाए गए वोटरों को फॉर्म-8 (जो शिफ्टेड वोटरों के लिए होता है) भरने की अनुमति दे या फिर उनके नाम बहाल करने के लिए कोई अलग कानूनी तंत्र या फॉर्म तैयार करे।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माणों और खतरनाक भवनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माणों तथा मास्टर प्लान दिल्ली (एमपीडी) और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शहरव्यापी अभियान लगातार जारी है। भवन निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से निगम के सभी 12 ज़ोनों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज की कार्रवाई के दौरान निगम द्वारा 26 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई तथा भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 8 संपत्तियों को सील किया गया। वहीं, कल की कार्रवाई के दौरान 23 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और 7 संपत्तियों को सील किया गया। निगम अपने अधिकार क्षेत्र में निरंतर निगरानी बनाए हुए है तथा चिन्हित उल्लंघनों के विरुद्ध निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। आज के अभियान के अंतर्गत पहाड़गंज, सीतिपुरा, करोल बाग और निमड़ी कॉलोनी सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। ये कार्रवाईयां अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने और भवन निर्माण संबंधी नियमों



के उल्लंघन को रोकने के लिए निगम द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। दिल्ली नगर निगम ने दोहराया कि उसके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखें तथा मास्टर प्लान दिल्ली,

भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। निगम का यह अभियान सभी 12 ज़ोनों में आगे भी जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाने, खतरनाक भवनों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जनसुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले उल्लंघनों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ने की आशंका है।

ईधन और बिजली की कीमतों का असर परिवहन पर भी

देवेंद्र यादव ने ईधन और बिजली से जुड़ी थोक महंगाई दर के 25.85 प्रतिशत तक पहुंचने का हवाला देते हुए कहा कि ऊर्जा की लागत बढ़ने का असर परिवहन, उत्पादन और माल ढुलाई पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन और माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, तो इसका प्रभाव बाजार में पहुंचने वाली वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि महंगाई का दबाव बढ़ने से आम लोगों के आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण की किस्तों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, ब्याज दरों और ऋण की किस्तों में बदलाव मौद्रिक नीति, बैंकों की दरों तथा संबंधित ऋण की शर्तों पर निर्भर करता है।

बचत और बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा असर

यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करना कठिन हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमित आमदनी के बीच आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ने से परिवारों की जमा पूंजी पर दबाव पड़ रहा

है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर केवल बाजार में सामान खरीदने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

वैश्विक परिस्थितियों और सरकारी नीतियों पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार कच्चे तेल और उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के लिए होम्सु जलडमरूमध्य से जुड़ी परिस्थितियों को जिम्मेदार बता रही है। उन्होंने इस संबंध में सरकार की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई के घरेलू कारणों और आर्थिक नीतियों की भी समीक्षा होनी चाहिए। यादव ने आरोप लगाया कि बड़े औद्योगिक घरानों को दिए गए कर्ज में राहत और सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का बोझ अंततः आम जनता पर पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने और गरीब, निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की मांग की। नोट: थोक महंगाई दर में वृद्धि और उसका आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में दिए गए राजनीतिक आरोप देवेंद्र यादव के बयान पर आधारित हैं। आंकड़ों तथा वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग से की जानी चाहिए।

हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक के पेश न होने पर जेल अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जेल से पेश न होने पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मलिक को कोर्ट के सामने वचुंअली पेश किया जाना था।, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में इस मामले में संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगी जाए। सुनवाई के दौरान 22 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा था कि यासिन मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के संपर्क में था, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी। एनआईए ने कहा था कि यासिन मलिक इन संपर्कों का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद फैलाने के लिए करता था। एनआईए की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामा में कहा गया है कि यासिन मलिक के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से नजदीकी संबंध थे और उसने हवाला जैसे गैरकानूनी तरीके से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 मई, 2022 यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और 10 लाख का जुर्माना, धारा 18 के तहत 10 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, धारा 20 के तहत 10 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत 5 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने यासिन

मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 10 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि यासिन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी। यासिन मलिक ने 10 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। 16 मार्च, 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद, सैयद सलाहूद्दीन, यासिन मलिक, शम्बीर शाह और मसत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताफ अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आल पार्टी हुर्रियत काफ़्रेस की स्थापना की गई। एनआईए के मुताबिक हाफिद सईद ने हुर्रियत काफ़्रेस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया।

हंसराज कॉलेज में 16-17 अक्टूबर को सजेगी गरबा और डाडिया की महफिल

नई दिल्ली,एजेंसी। नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में 16 और 17 अक्टूबर को ‘दिल्ली गरबा महोत्सव 2026’ का आयोजन किया जाएगा। नित्य अनुभूति मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से आयोजित इस दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव में गरबा, डाँडिया, संगीत और विभिन्न व्यंजनों का संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम शाम छह बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा। महोत्सव में बॉलीवुड फिल्मों ‘तलाश’ और ‘हैप्पी न्यू ईयर’ सहित कई फिल्मों में पार्श्व गायन कर चुके गायक रवीन्द्र उपाध्याय विशेष संगीतमय प्रस्तुति देंगे। उनके गीतों के साथ गरबा और डाँडिया की पारंपरिक धुनें उत्सव के आकर्षण को बढ़ाएंगी। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में दिल्ली के जाने-माने डीजे गुजराती लोकसंगीत, पारंपरिक गरबा धुनों और इंडी म्यूजिक के मिश्रण से समां बांधेंगे। इसके अलावा, महोत्सव में विशेष फ्यूज कोर्ट भी बनाया जाएगा, जहां आगंतुक भारतीय और कॉन्ट्रेंटल फूड कोर्ट का आनंद ले सकेंगे। आयोजकों का कहना है कि महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, नवरात्रि की आध्यात्मिक भावना और सामूहिक उत्सव की उमंग को एक मंच पर लाना है। यह आयोजन दिल्लीवासियों, विशेषकर युवाओं और परिवारों को भारतीय लोकसंस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

जेएनयू की 11 छात्राओं की शिकायतों पर भाजपा महिला मोर्चा ने राष्ट्रीय महिला आयोग से की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की 11 छात्राओं की ओर से कथित दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के मामले में कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकुर को पत्र सौंपा है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने बुधवार को बताया कि उन्होंने पार्टी की पांच महिला सांसदों और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मामले को संज्ञान लेने और छात्राओं की शिकायतों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। चौधरी ने कहा कि जेएनयू की 11 छात्राओं ने साहस दिखाते हुए डॉ. बिमोल अकोइजाम के खिलाफ लिखित शिकायतें दर्ज करवाई थीं। उनके अनुसार, विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने जांच के बाद शिकायतों को सही पाया और संबंधित प्रोफेसर को विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा कि छात्राओं की शिकायतों और विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की जांच के निष्कर्षों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कदम उठाने की अपील की। चौधरी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस और उसके नेताओं की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान कांग्रेस सांसद से जुड़ा यह मामला सामने आने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है। भाजपा की ओर से मांग की गई है कि छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से आग्रह किया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए।

छठ घाटों पर बेहतर रोशनी की व्यवस्था, सभी 250 वार्डों में लगेंगी स्ट्रीट लाइट : एमसीडी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने छठ घाटों पर बेहतर रोशनी के लिए 250 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा के दौरान स्वच्छ, सुरक्षित और रोशनी से जगमगाते घाट उपलब्ध कराने के लिए एमसीडी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। घाटों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ने सभी 250 वार्डों में दो-दो छठ घाटों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट जारी करने के साथ ही विद्युत विभाग को घाट चिह्नित कर रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा घाटों और उनके आसपास की सड़कों व गलियों को दुरुस्त करने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फागिंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को सभी तैयारियों संपन्न रहते पूरी करने को कहा है। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि छठ महापर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह और शाम घाटों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे में घाटों के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी पर्याप्त रोशनी और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों और उनके आसपास की सड़कों व गलियों का निरीक्षण कर जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां समय रहते काम पूरा कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो। छठ घाटों और आसपास के इलाकों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने और कूड़े का नियमित उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक नजर

पति की प्रेमिका की हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार

नोएडा। पति की प्रेमिका को गला दबाकर हत्या करने वाली महिला को थाना फेस- 2 पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मोडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने बुधवार को बताया कि थाना फेस-दो क्षेत्र के याकूपपुर गांव में एक युवती का शव एक मकान के अंदर पड़ा हुआ मिला था। जिस घर में युवती का शव मिला था उसमें एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई की महिला को गला दबाकर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया, तथा घटना की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को शाम को थाना पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाली शीला कुमारी पत्नी नतिन मूलनिवासी जनपद कासगंज को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की उम्र 24 वर्ष है। उन्होंने बताया कि पूरुषाक्ष के दौरान गिरफ्तार अभियुक्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 20 अक्टूबर 2025 को नतिन पुत्र मुकेश के साथ हुई थी। महिला के अनुसार उसके पति के मृतका मनीषा से प्रेम संबंध थे। उसका पति मनीषा को उसके कमरे में लेकर आया तथा एक साथ रखने लगा। इस बात को लेकर मनीषा से वह ईर्ष्या करने लगी। महिला के अनुसार उसका पति 4 अक्टूबर को कासगंज जनपद किसी काम से चला गया। इसी बीच उसने 5 अक्टूबर को मनीषा की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से चली गई।

फरीदाबाद में नकाबपोश

हमलावरों ने तोड़ी युवक की टांगें

फरीदाबाद । फरीदाबाद की डबुआ कालोनी में दर्जनभर नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को भीका बजाए घर लिया। पहले उसे सड़क पर गिराकर जमकर लाठी-डंडों से पीटा, इसके बाद पैर पकड़कर सड़क पर काफी दूर तक घसीटा। हैरानी की बात यह रही कि आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यह पूरी घटना बाजार की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के भाग जाने के बाद परिजनों ने बेसुध युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पता चला कि लाठी-डंडों के वार से उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, चार्लू युवक सागर (22) डबुआ कालोनी का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में काम करता है। मंगलवार रात वह अपने दोस्त के साथ दुकान से दूध की थैली लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान डबुआ-गाजीपुर में मसिन्द के पास नकाबपोश बदमाशों ने उसे घर लिया। बदमाशों ने डंडों और सिरियों से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले को देखकर उसका दोस्त वहां से भाग गया। सागर खुद को संभाल नहीं पाया और हमलावरों ने उसे सड़क पर गिराकर बेहमी से पीटा। डबुआ थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले सागर के दोस्त का कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान सागर भी वहां मौजूद था। पुलिस इसी पुराने विवाद के कोण से भी मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, सागर का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस टीम उसके बयान दर्ज करने के लिए रवाना कर दी गई है। परिजनों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।

डांडिया नाइट में खूब थिरके महिलाएं, पुरुष

गुरुग्राम। रंग-बिरंगे कपड़ों, संगीत की धुनों और डांडिया की खनक से सेक्टर-83 स्थित लाइफस्टाइल होम्स सेंट्रल पार्क में उत्सव का बड़ा माहौल बन गया। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी एनवायरो ने एजिस मीडिया के साथ मिलकर शाम के समय निवासियों के लिए डांडिया उत्सव किया। इस उत्सव में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने गरबा और डांडिया किया, लावज म्यूजिक का आनंद लिया और त्योहारों के खास पकवानों का स्वाद चखा। हर उम्र के परिवारों, पड़ोसियों और दोस्तों ने मिलकर डांस किया, जिससे सोसाइटी के सांख्य स्थान उत्सव के रंग में रंग गए। उत्सव को और खासा स्थान के लिए स्टॉल लगाने की विशेष व्यवस्था की गई। निवासियों को खास छूट पर स्टॉल बुक करने का मौका मिला। इससे स्थानीय कारोबारियों और विक्रेताओं को अपने उत्पाद दिखाने और सोसाइटी के लोगों से सीधे जुड़ने का अवसर मिला। परंपरा, मनोरंजन और खाना-पान को एक साथ जोड़ने वाले इस डांडिया उत्सव के जरिए एनवायरो ने यह संदेश दिया कि उसकी भूमिका केवल सुविधाओं के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बीच बेहतर संबंध बनाने और समुदाय को मजबूत करने में भी है। इन आयोजनों ने निवासियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ाया और उन्हें मिलकर त्योहार मनाने का अवसर दिया। एम3एम द्वारा गुरुग्राम में नवरात्रि के मौके पर डांडिया रास उत्सव 2.0 का आयोजन 16 से 18 अक्टूबर 2026 तक एम3एम 65वां अनेक्यू सेक्टर-65 में किया जाएगा। तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव में पारंपरिक गरबा और डांडिया के साथ लावज म्यूजिक, डीजे और कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। पहले दिन 16 अक्टूबर को डीजे तरण, डीजे दीपिका पांडे, गायिका राखी खीना और एरा ऑफ जैस्मिन प्रस्तुति देंगे।

मढी के विद्यार्थियों ने किया आईआईटी दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण



कार्यशाला में आईआईटी दिल्ली में अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी ध्रुव और वैभव ने मढ़ी के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संस्थान में पढ़ाई की व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा के महत्व, प्रवेश प्रक्रिया और विद्यार्थियों को मिलने वाले शैक्षणिक

अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देकर उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने, नियमित अध्ययन करने और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसरसर पर मेवात विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी मुफीद, विद्यालय के प्रधानाचार्य

फरीदाबाद: पीजी परीक्षा में ईएसआईसी कॉलेज के 26 छात्रों ने हासिल की टॉप-3 रैंक

फरीदाबाद। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा घोषित प्रोस्टेयट्रोजेन (पीजी) बैच-2023 के परीक्षा परिणामों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के 26 विद्यार्थियों ने विभिन्न विशेषज्ञताओं में शीर्ष तीन स्थानों पर जगह बनाकर अगनी प्रतीक्षा का परिचय दिया और संस्थान का गौरव बढ़ाया। परीक्षा परिणामों में डमेंटोलॉजी विषय में डॉ. अनमोल गोदारा ने 800 में से 599 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। ऑपथल्मोलॉजी में डॉ. जूही अरोड़ा ने 581 अंकों के साथ प्रथम तथा डॉ. आस्था खडेलवाल ने 580 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रेडियोलॉजी में डॉ. अरुणा थॉमस ने 568 अंकों के साथ प्रथम रैंक हासिल की। एनेस्थिस्थियोलॉजी में डॉ. विनीता किस्कू ने 571 अंकों के साथ द्वितीय तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विषय में डॉ. आर. भार्गवी ने 566 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में पैथोलॉजी में डॉ. मानसी कुशवाहा ने 558 अंकों के साथ प्रथम, डॉ. आशना दीप ने 548 अंकों के साथ द्वितीय तथा डॉ. अलिशी हांसि ने 535 अंकों के साथ तृतीय स्थान हासिल किया। जनरल मेडिसिन में डॉ. तेजस मेंहदीरता ने 554 अंकों के

साथ प्रथम तथा डॉ. कृष्ण कुमार ने 547 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जनरल सर्जरी में डॉ. बोब्बा उदय किरण ने 543 अंकों के साथ प्रथम और ईएनटी में डॉ. अर्जुन अग्रवाल ने 540 अंकों के साथ प्रथम तथा डॉ. रजनी रानी ने 517 अंकों के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया। अन्य विशेषज्ञताओं में बायोकेमिस्ट्री में डॉ. प्रबिन अग्रवाल ने 557 अंकों के साथ तृतीय, रेस्पिरटरी मेडिसिन में डॉ. शालू शर्मा ने 555 अंकों के साथ तृतीय, फिजिकल मेडिसिन एंड रीहैबिलिटेशन (पीएमआर) में डॉ. अखिलेश ने 539 अंकों के साथ प्रथम, डॉ. आनंद कुमार कौशल ने 466 अंकों के साथ द्वितीय तथा डॉ. जतिन कुमार होंगरा ने 439 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। एनाटॉमी में डॉ. स्वाति शर्मा ने 519 अंकों के साथ प्रथम तथा डॉ. विद्यावती पटेलवारी ने 492 अंकों के साथ तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, आईएचबीटी में डॉ. पूनम सैनी ने 511 अंकों के साथ प्रथम, कम्युनिटी मेडिसिन में डॉ. अनम स्नेहा किरण ने 516 अंकों के साथ द्वितीय तथा पीडियाट्रिक्स में डॉ. रुचि पांचाल ने 516 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ऑर्थोपेडिक्स में डॉ. रोहित रावल ने 516 अंकों के साथ तृतीय तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग में डॉ. तन्वी मिश्र ने 556 अंकों के साथ तृतीय स्थान हासिल किया।

अवैध पटाखों के भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई, गोदाम से 7270 किलोग्राम पटाखे बरामद



मांगे, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के दौरान गोदाम के दो कमरों में अलग-अलग ब्रांड के पटाखे पेटियों और खुले रूप में रखे मिले। पुलिस टीम ने पूरी बरामदगी को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि संचालक ने उक्त गोदाम किराये पर लिया

हुआ था। उसके पास पहले पटाखे बेचने का लाइसेंस था, जो कि 2025 में समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद उसने झुज्जर और रोहतक क्षेत्र से पटाखे खरीदकर गोदाम में भंडारण किया हुआ था। पुलिस टीम द्वारा अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि पटाखों की खरीद, भंडारण और वित्त्र की संबंधित तथ्यों का पता लगाया जा सके।

**किसानों की बागवानी खेती से बढ़ रही आमदनी,
टमाटर व बैंगन की खेती से किसान मालामाल**

नूह। नूह जिले में किसानों की सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा सेवा-सेतु संकल्प अभियान सरकारकम परिणाम दे रहा है। बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान पारंपरिक खेती के साथ टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों की खेती को अपनाने एग बेहतर मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। विभाग की ओर से मिलने वाला अनुदान किसानों को खेती की लागत कम करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद कर रहा है। जिले के पांच किसानों की सफलता अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सरकारी का देश की खेती को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी आमदनी बढ़ाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। सेवा-सेतु संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं, अनुदान के नियमों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। गांव

बढ़कालीमुद्दीन के किसान हनीफ ने एक एकड़ भूमि में टमाटर की खेती कर लगभग डेढ़ लाख रुपये का मुनाफा अर्जित किया। बागवानी विभाग की योजना के तहत उन्हें 30 हजार रुपये का अनुदान मिला। सरकारी सहायता से उन्हें खेती में आर्थिक सहयोग मिला।

गांव बढ़कालीमुद्दीन के किसान असरुद्दीन ने टमाटर की खेती से लगभग एक लाख 60 हजार रुपये का मुनाफा कमाया। उन्हें बागवानी विभाग की ओर से 40 हजार 200 रुपये का अनुदान मिला। इसी गांव के किसान मोहम्मद कासिम ने भी एक एकड़ में टमाटर की खेती कर लगभग एक लाख 50 हजार रुपये का मुनाफा अर्जित किया। कासिम को विभाग की योजना के तहत 40 हजार 200 रुपये की आर्थिक सहायता मिली।

गांव बढ़कालीमुद्दीन के किसान लियाकत ने बागवानी फसलों से लगभग दो लाख रुपये का मुनाफा कमाया। उन्हें विभाग की ओर से 65 हजार रुपये का अनुदान मिला। उनकी सफलता से दूसरे किसानों को भी बागवानी खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाने की प्रेरणा मिल रही है।

पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, चार गिरफ्तार

गुरुग्राम। अपराध शाखा सेक्टर-65 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बना रहे तीन हिंसाखण्ड बंदमशाओं को मुम्बई के बाद गिरफ्तार किया है। मुम्बई में दो बंदमशाओं के पैर में गोली लगी, जबकि बंदमशाओं की गोली से एक पुलिसकर्मी की घायल हो गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि इस नेटवर्क के चौथे आरोपी को भी पकड़ लिया गया जो इनको ड्रग्स सप्लाई करता था।

पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 136 ग्राम एमडीएमए एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और खाली खोल बरामद हुआ है। नौ अन्तर्दूर की रात क्रांज ब्रॉच को सूचना मिली थी कि तीन हथियारबंद युवक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। सूचना पर नानौली उमरपुर से सेक्टर-62 रोड पर नाकाबंदी की गई। रात करीब 11 बजे बाइक पर आए 3 युवकों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक भगाते रुकने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक गोली पुलिस वाहन पर लगी और दूसरी एक पुलिसकर्मी की बाजू में लगी। पुलिस ने आत्मरक्षाम में जवाबी फायरिंग की, जिसमें मार्फत उर्फ मारु (32) और फूल बाबू शेख (26) के पैर में गोली लगी। तीसरे आरोपी

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कठोर कैद

फरीदाबाद । नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से मामले की प्रभावी जांच, साक्ष्यों के संकलन और अदालत में गई मजबूत पेश्वी के मिलने से मामले को चिन्हित श्रेणी में रखा गया, जिससे परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी हाकमचंद के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित अपराधों के आरोप में थाना महिला वल्लभगढ़ में 16 सितंबर 2022 को मामले दर्ज किया गया था। मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 10, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 व 506 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को 14 सितंबर 2022 को ही गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने आगे बताया कि मामले के जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए और कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों की गवाही हुई। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुडला की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 323 व 506 आईपीसी में 2 साल व दस हजार रुपए जुर्माना तथा 25 शस्त्र अधिनियम के एक साल व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।



प्रताप केसरी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से एक कार के चोरी किए हुए चार टायर, चोरी का लैपटॉप, अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त

बदमाश के ऊपर पूर्व में चार मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी दिन में टैक्सी चलाता है, तथा रात में चोरी की वारदात करता है।

युवक को अपहरण करके ले जा रहे थे, रास्ते में एकसीडेंट हुआ तो उतरकर भागा पीड़ित

गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-31 ने अपहरण के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नितिन (20 वर्ष) निवासी गांव पथराव जिला मेहेन्द्रगढ़ और खुश उर्फ मंजीत (19 वर्ष) निवासी गांव मारौत, जिला झज्जर के रूप में हुई है। सहायक

पुलिस आयुक्त अपराध नवीन शर्मा ने बुधवार को बताया कि दोनों आरोपी वर्तमान में गुरुग्राम में रह रहे हैं। दोनों को सनसिटी हिंसा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सात अक्टूबर 2026 को पुलिस चौकी के लेक्टर-93 को सूचना मिली थी कि दोनो आरोपी को सैनी नामक युवक को 'पांच-छह युवक मारपीट करके सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी में डालकर ले गए हैं'। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अगले दिन आठ अक्टूबर को पीपुड़ के पिता ने लिखित शिकायत दी कि उनका बेटा विककी उर्फ सैनी नामक युवक को लेकर उसका प्रिंस नामक युवक से झगड़ा हो गया था। तब से प्रिंस और उसके साथी 'रंजिश' रखते थे। सात अक्टूबर को

शाम करीब छह बजे विक्की अपने दोस्त से मिलने गढ़ी गांव में गया था। रात 10 बजे उसके दोस्त ने फोन पर बताया कि गढ़ी लेबर चौक पर सफेद रंग की क्रेटा में आए पांच-छह लड़कों ने विक्की को पीटकर गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया है। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-10 में मामला दर्ज किया गया।

अब पुलिस ने आरोपियों का काबू किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के दौरान अन्य साथी आरोपियों के बारे में अहम जानकारी नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नितिन गुरुग्राम में खुद भी पैडिंग टैक्सी चलाता है। कुछ दिनों पहले पीडित विक्की और उसके दोस्त सचिन उर्फ कालू का नितिन और उसके साथी प्रिंस से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में उन्होंने अहमरघर की योजना बनाई। सात अबतूर की रात वे क्रेटा में पीडित को हिसार की तरफ ले जा रहे थे। हांसी-बरवाल रोड पर तेज रफ्तार के कारण गाड़ी सामने आने से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी दौरान पीडित मौका पाकर गाड़ी से भाग निकला।



श्रीकूल शंख (37) को भी मौके पर काबू कर लिया गया। तीनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया जिले के रहने वाले हैं। मुठभेड़ में नौ राउंड फायरिंग हुई। छह राउंड बदमाशों ने और तीन पुलिस ने किए। गायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 11 अक्टूबर को इस्तेमाल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि इन्हें 'ड्रग्स कबीर' नामक युवक सप्लाय

करता है। पुलिस ने कबीर निवासी बाली मुर्शिदाबाद को भी 11 अक्टूबर को सेक्टर-62 से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि फूल बाबू शेख पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में पहले से इनाम घोषित था। मार्फत पर चार केस, फूल बाबू पर दो और श्रीकुल पर एक केस दर्ज हैं। आरोपी मार्फत को कोर्ट से 19 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है।

जंतर-मंतर से दूर होते प्रतिरोध के ठिकाने

महेन्द्र तिवारी

लोकतंत्र की जीवंतता केवल इस बात से तय नहीं होती कि संसद के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कितनी सार्थक बहस होती है, बल्कि इसकी असली कसौटी यह है कि संसद के बाहर सड़कों पर आम नागरिक की आवाज को कितनी गंभीरता और सहजता से सुना जाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल में स्थित जंतर मंतर पिछले 33 वर्षों से इसी लोकतांत्रिक चेतना, जन आक्रोश और नागरिक उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। किंतु अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जंतर मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया है। 28 अप्रैल 2022 के पुराने स्थायी आदेश में संशोधन करते हुए अब राजधानी में धरना और प्रदर्शन के लिए तीन नए स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के कड़कड़झूमा स्थित व्यावसायिक केंद्र मैदान शामिल हैं। प्रशासन के इस एक निर्णय ने तीन दशकों से चली आ रही प्रतिरोध की एक पूरी परंपरा को विराम दे दिया है और साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के बीच के द्वंद पर एक नई बहस छेड़ दी है।

जंतर मंतर का यह परिसर केवल 18वीं सदी के खगोलीय यंत्रों का स्मारक मात्र नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका था। वर्ष 1993 से लेकर 2026 तक के अपने 33 वर्षों के सफर में इस छोटे से मार्ग ने अनगिनत ऐतिहासिक बदलावों की नौबत रखी। चाहे वर्ष 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन हो, वर्ष 2012 में निर्भया कांड के बाद उमड़ा युवाओं का स्वतःस्फूर्त जनसैलाब हो, वर्ष 2015 में पूर्व सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन आंदोलन हो या फिर वर्ष 2023 में महिला पहलवानों का लंबा संघर्ष, जंतर मंतर ने हर वर्ग की पीड़ा को राष्ट्रीय पटल पर रखने का मंच प्रदान किया। देश के सुदूर कोनों से आने वाले किसानों, मजदूरों, छात्रों, शिक्षकों और वंचित वर्गों के लिए यह स्थान एक ऐसी उम्मीद की तरह था, जहाँ खड़े होकर वे सीधे सत्ता के शीर्ष से संवाद करने का अहसास पाते थे। संसद भवन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ उठने वाली हर आवाज की गूंज नीति निर्माताओं के कानों तक आसानी से पहुँच जाती थी। इस ऐतिहासिक स्थल से



प्रदर्शनों को हटाने के पीछे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अपने ठोस तर्क हैं। तात्कालिक कारणों पर नजर डालें तो वर्ष 2026 के जून और जुलाई माह में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर लगभग 36 दिनों तक चला विशाल छात्र आंदोलन इस फैसले का मुख्य आधार बना। उस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की सीमित क्षमता के विपरीत 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी जुट गए थे। जब इस भारी भीड़ ने संसद भवन की ओर कूच करने का प्रयास किया, तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस तथा छात्रों के बीच हुई झड़पों में 118 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों छात्र घायल हुए। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और युवा संगठनों द्वारा फिर से जंतर मंतर पर बड़े घेराव की तैयारी की जा रही थी। नए संसद भवन और कर्तव्य पथ के आसपास अति विशिष्ट व्यक्तियों के निरंतर आवागमन

और संवेदनशील मंत्रालयों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का मानना है कि इतनी कम दूरी पर अनियंत्रित भीड़ का जुटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है। सुरक्षा के अलावा स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों की दैनिक परेशानियां भी इस बदलाव का एक बड़ा कारण बनी हैं। जंतर मंतर राजधानी के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस और जनपथ के ठीक बगल में स्थित है। जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रदर्शन होता था, तो एहतियात के तौर पर आसपास की मुख्य सड़कें और रेल के भूमिगत स्टेशन बंद कर दिए जाते थे। इससे न केवल घंटों लंबा यातायात जाम लगता था, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों की गाड़ियां छूट जाती थीं। स्थानीय व्यापार मंडलों ने लंबे समय से यह शिकायत की थी कि लगातार होने वाले धरनों और नाकेबंदी के कारण कनॉट प्लेस के व्यापार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय

ने भी पूर्व में यह सुझाव दिया था कि प्रदर्शनों के लिए ऐसी खुली और बड़ी जगह तलाशी जानी चाहिए जहाँ आम जनजीवन प्रभावित न हो तथा प्रदर्शनकारियों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। किंतु इस प्रशासनिक सुविधा के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो नागरिक अधिकार संगठनों और संविधानविदों की चिंताएं अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं। राजधानी में सत्ता के केंद्र से जन आंदोलनों को दूर धकेलने की यह प्रवृत्ति नई नहीं है, बल्कि पिछले चार दशकों में विरोध का पता तीन बार बदला जा चुका है। जब 1988 तक इंडिया गेट के पास स्थित बोट क्लब देश के सबसे बड़े प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से संसद और राष्ट्रपति भवन सीधे दिखाई देते थे। अक्टूबर 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब 5 लाख किसानों ने एक सप्ताह तक बोट क्लब पर डेरा डाला, तो सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देकर वहां प्रदर्शनों पर

हूती आंदोलन, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, उत्तरी यमन के जैदी शिया समुदाय से उभरा। इसके समर्थकों ने राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक-सांस्कृतिक हानियों पर रखे जाने के विरुद्ध आवाज उठाई। समय के साथ यह आंदोलन एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन बन गया। हालांकि इसकी जड़े यमन की घरेलू परिस्थितियों में हैं लेकिन इसके सैन्य विस्तार और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के साथ संघर्ष ने देश की अस्थिरता को और बढ़ाया। वर्ष 2014 में हूतियों द्वारा राजधानी सना पर कब्जा करना संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की स्थिति कमजोर हुई और राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया बाधित हो गई। सऊदी अरब ने इस घटनाक्रम को अपनी दक्षिणी सीमा के निकट गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा। यमन के साथ लंबी साझा सीमा होने के कारण सऊदी अरब को आशंका थी कि हूतियों का विस्तार उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। हूतियों द्वारा सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा सैन्य ठिकानों एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाए जाने से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने हूतियों की बढ़ती शक्ति को रोकने और मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को समर्थन देने के उद्देश्य से सैन्य हस्तक्षेप किया।

यमन में सऊदी-हूती संघर्ष

डॉ. प्रियंका सौरभ

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष पश्चिम एशिया की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। यह संघर्ष यमन के लंबे समय से जारी गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय शक्ति-संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हितों का परिणाम है। वर्ष 2014 में हूती विद्रोहियों द्वारा यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद संघर्ष ने व्यापक रूप ले लिया। मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के हस्तक्षेप ने इसे घरेलू राजनीतिक संकट से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती में बदल दिया। यद्यपि कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम करने की कोशिशें हुई हैं, फिर भी यह संघर्ष मानवीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इस संघर्ष का पहला प्रमुख कारण यमन में राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर शासन व्यवस्था है। वर्ष 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनके उत्तराधिकारी अब्दरब्बुह मंसूर हादी एक प्रभावी और समावेशी शासन स्थापित करने में सफल नहीं हो सके। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और कमजोर सरकारी संरक्षाओं ने राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। परिणामस्वरूप, विभिन्न सशस्त्र समूहों और राजनीतिक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे हूती आंदोलन के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनीं। दूसरा प्रमुख कारण हूती आंदोलन की राजनीतिक और सामाजिक शिकायतें हैं।

हूती आंदोलन, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, उत्तरी यमन के जैदी शिया समुदाय से उभरा। इसके समर्थकों ने राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक-सांस्कृतिक हानियों पर रखे जाने के विरुद्ध आवाज उठाई। समय के साथ यह आंदोलन एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन बन गया। हालांकि इसकी जड़ें यमन की घरेलू परिस्थितियों में हैं लेकिन इसके सैन्य विस्तार और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के साथ संघर्ष ने देश की अस्थिरता को और बढ़ाया। वर्ष 2014 में हूतियों द्वारा राजधानी सना पर कब्जा करना संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की स्थिति कमजोर हुई और राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया बाधित हो गई। सऊदी अरब ने इस घटनाक्रम को अपनी दक्षिणी सीमा के निकट गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा। यमन के साथ लंबी साझा सीमा होने के कारण सऊदी अरब को आशंका थी कि हूतियों का विस्तार उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। हूतियों द्वारा सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा सैन्य ठिकानों एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाए जाने से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने हूतियों की बढ़ती शक्ति को रोकने और मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को समर्थन देने के उद्देश्य से सैन्य हस्तक्षेप किया। हालांकि इसके हस्तक्षेप का घोषित उद्देश्य यमन की सरकार को बहाल करना था लेकिन लंबे समय तक चले सैन्य अभियान से संघर्ष का समाधान और जटिल हो गया। इस संघर्ष का व्यापक भू-राजनीतिक कारण ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा है। ईरान ने हूती आंदोलन को विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक, तकनीकी और सैन्य समर्थन दिया है। सऊदी अरब



इसे अपनी दक्षिणी सीमा के निकट ईरानी प्रभाव बढ़ने के रूप में देखता है। हालांकि हूती आंदोलन की अपनी घरेलू जड़ें और स्वतंत्र राजनीतिक प्राथमिकताएँ भी हैं, फिर भी ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता ने संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय आयाम प्रदान किया। इस प्रकार यमन आंतरिक राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ पश्चिम एशिया की शक्ति-प्रतिस्पर्धा का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया।

संघर्ष के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हुए हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मानवीय संकट के रूप में दिखाई देता है। लंबे समय तक चले युद्ध ने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया है तथा खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं को गंभीर बनाया है। अस्पतालों, विद्यालयों, जलापूर्ति प्रणालियों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुँचा है। कमजोर शासन व्यवस्था और आर्थिक संकट ने आम नागरिकों के जीवन को और कठिन बना दिया है। ऐसी परिस्थितियाँ उग्रवादी संगठनों के विस्तार और अवैध गतिविधियों के लिए भी अवसर पैदा कर सकती हैं। दूसरा प्रमुख प्रभाव समुद्री सुरक्षा पर पड़ा है। यमन की भौगोलिक स्थिति बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के निकट होने के कारण अत्यंत रणनीतिक है। यह जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज नहर के माध्यम से एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। हूतियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों और समुद्री यातायात को निशाना बनाए जाने से अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा प्रभावित हुई है। विशेष रूप से 2023 के अंत से लाल सागर में बढ़ते हमलों ने कई शिपिंग कंपनियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से जहाजों के गुजरने के कारण यात्रा का समय, ईंधन खर्च और परिवहन लागत बढ़ गई। तीसरा प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ा है। पश्चिम एशिया वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है और यहाँ की सुरक्षा संबंधी घटनाएँ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2019 में सऊदी अरब के

अबकैक और ख्रूस तेल प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों ने महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की कमजोरियों को उजागर किया। इन हमलों को केवल सऊदी-हूती संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम मानना उचित नहीं होगा लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े व्यापक जोखिमों को स्पष्ट किया। ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की आशंका से तेल की कीमतों में अनिश्चितता, बीमा लागत में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान का खतरा बढ़ जाता है। चौथा प्रभाव क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ा है। संघर्ष ने ईरान और सऊदी अरब के बीच अविश्वास को गहरा किया तथा पश्चिम एशिया में बाहरी शक्तियों की भूमिका को बढ़ाया। मिसाइलों, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल से सैन्य प्रतिस्पर्धा तेज हुई है। इससे क्षेत्रीय देशों को अपनी रक्षा प्रणालियों, खुफिया क्षमताओं और समुद्री सुरक्षा पर अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, संघर्ष का विस्तार व्यापक क्षेत्रीय तनाव को जन्म दे सकता है, जिससे आतंकवाद-रोधी सहयोग और अन्य कूटनीतिक प्रयास भी प्रभावित होते हैं। वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। लाल सागर और स्वेज नहर का मार्ग अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में असुरक्षा से माल की ढुलाई महँगी हो सकती है, वस्तुओं की आपूर्ति में देरी हो सकती है और आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए खाद्य पदार्थों, ईंधन और औद्योगिक वस्तुओं की बढ़ती परिवहन लागत आर्थिक चुनौतियों को और गंभीर बना सकती है। इस संघर्ष का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया और क्षेत्रीय कूटनीति में निहित है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हूती आंदोलन, मान्यता प्राप्त यमनी सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सार्थक वार्ता को आगे बढ़ाना आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सत्ता-साझेदारी, सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

विचार

चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ते बाजारीकरण का संकट

चंद्रकांत लहरिया

भारतीय निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले चार दशकों में बने सामाजिक और नैतिक संकट का सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत अस्पताल क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों के प्रवेश से हुई और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वेंचर कैपिटल एवं निजी निवेश से इसने रफ्तार पकड़ी। यह संकट ढाँचागत है। निजी स्वास्थ्य सेवा के विकास ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनमें डॉक्टरों से अस्पतालों, दवा कंपनियों और संबंधित हितधारकों के लिए मुनाफा कमाने की अपेक्षा की जाती है। उपचार निर्णय, जोकि रोगी की जरूरत से निर्धारित होना चाहिए, उस पर व्यावसायिक प्रोत्साहनों और चिकित्साकरण का प्रभाव हावी हो गया है। इस परिवर्तन ने डॉक्टर-रोगी संबंध को बदल डाला। चिकित्सक अब मात्र स्वतंत्र पेशेवर नहीं रह गया जो रोगी के प्रति जवाबदेह हो। कई डॉक्टर नैतिक बने हुए हैं और कई कॉरपोरेट अस्पताल भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं, तथापि ‘प्रोत्साहन रूपी लालच’ पेशेवर आजादी कायम रखना मुश्किल कर देता है। मसलन कॉर्पोरेट अस्पतालों में डॉक्टरों को वेतन तो मिलता है, लेकिन मालिकों की अपेक्षा होती है कि वे अधिकाधिक कमाई कर दिखाएं, रोगी संख्या बढ़ाएं, जांच, भर्ती और इलाज प्रक्रियाओं में अधिक मुनाफा बनाएं। भारत में स्वास्थ्य सेवा के कॉर्पोरेटीकरण पर एक शोध में उपार्जन लक्ष्य, डॉक्टरों सलाह को अस्पताल भी में परिवर्तित करने या एक-दो दिन वाले इलाज को लंबा खींचने को दबाव बनाने और घटती स्वायत्तता को दर्ज किया है।

ऐसे रंग-ढंग ने ‘अच्छे’ डॉक्टर की परिभाषा बदल दी है। जो चिकित्सक मरीजों को नेक डॉक्टरी सलाह देते हैं, बीमारी पर सावधानी भरा इंतजार करने की सलाह देते हैं या किसी महंगी प्रक्रिया से बचने की सलाह देते हैं, वे अधिक टेस्ट और उपचार करवाने वाले डॉक्टर की तुलना में कम पैसा कमाने में काम करता है। अस्पताल की निजी दवा विक्रेता दुकानें इस इकोसिस्टम का उदाहरण हैं। कई अस्पताल चुनिंदा ब्रांडों से भरी आंतरिक फार्मिसियां संचालित करते हैं, डॉक्टरों को वहां रखी दवाएं ही लिखने को कहा जाता है। इससे मरीज का क्रय चयन सीमित हो जाता है और हॉस्पिटल की कमाई बढ़ जाती है। पिछले 18 महीनों में मोटापा कम करने वाली दवाओं की बढ़ती मांग इस तनाव को दिखाती है। जोएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और उनसे जुड़ी दवाओं का फायदा सही में चुने गए मरीज को हो सकता है। फिर भी, सम्मेलनों और मेडिकल प्रचार शिविरों के जरिए की जाती इनकी आक्रामक मार्केटिंग पर सोचना जरूरी है। एक मेडिकल विशेषज्ञ ब्रांड एंवेसडर बनने की बजाय सुबुतों को समझने और व्याख्या करने वाला हो। उनकी भूमिका केवल यह बताना नहीं है कि दवा क्या कर सकती है, बल्कि यह बताना भी है कि कैसे इसकी जरूरत नहीं है, क्या अनिश्चितताएँ हैं, क्या-क्या बुरे असर और लागत है, कितने समय तक वास्तव में इलाज की जरूरत है, और दवा के बगैर कौन से उपचार ढंग का महत्त्व कायम है। कॉर्पोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाएं तेजी से मुख्य भूमिका में आ रही हैं। ये चिंताएं लंबे समय से चली आ रही हैं। 2018 में, समीरन नंदी, केशव देशराजु और संजय नागराल ने ‘स्वास्थ्य सेवा रक्षक या भक्षक ? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार’ नामक पुस्तक संपादित की है। इसमें हितों का टकराव, कॉर्पोरेट अस्पतालों के तौर-तरीके, दवा उत्पादक कंपनियों का प्रभाव, मेडिकल नियमन और व्यावसायिक नैतिकता की जांच की गई थी। आज भी इसकी प्रासंगिकता चिंताजनक है। चिकित्सा जात ने बार-बार इस समस्या की शिनाख्त तो की, लेकिन सुधार सीमित ही रहा। कमजोर नियमन मुख्य समस्या है। भारत में डॉक्टरों के लिए नैतिकता संहिता और दवा उत्पादन की मार्केटिंग का नियंत्रण करने वाले नियम हैं। रेफरल कमीशन, गलत प्रोत्साहन और व्यापारिक प्रभावों के नाना तरीकों पर रोक है। फिर भी, क्रियावन्धन एक समान नहीं और अक्सर कार्रवाई शिकायतों या घोटालों के बाद होती है, न कि व्यवस्थित निगरानी के जरिए। जब क्रियावन्धन ही अनिश्चित हो, तो नैतिक संहिता का कोई खास मतलब नहीं।

एक नजर

चोरी के पांच लाख रुपये वापस पाकर राजमिस्त्री के चेहरे पर लौटी मुस्कान



दरभंगा,एजेंसी। दरभंगा जिले के नेहरा थाना पुलिस ने राजमिस्त्री सुबोध दास को उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से चोरी हुए पांच लाख रुपये बुधवार को वापस सौंप दिए। न्यायालय के आदेश पर नेहरा थानाध्यक्ष मोती कुमार ने थाना परिसर में राशि उन्हें हस्तगत कराई। मेहनत की कमाई वापस मिलने पर सुबोध दास और उनके परिवर्जन के चेहरे पर खुशी छा गई। इसके बाद थानाध्यक्ष ने पुलिस सुरक्षा में उन्हें घर तक पहुंचाया। पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, मानवीय सूचना और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महज चार दिनों के भीतर चोरी की इस घटना का उद्बेदन कर लिया था। चोरी की पूरी राशि कोड़ा थाना क्षेत्र के जुरावांगंज निवासी प्रभु यादव के पुत्र ऋतिक कुमार के घर से बरामद की गई थी। 25 सितंबर को बहेड़ा थाना क्षेत्र की अमैठी पंचायत के नमती गांव निवासी राजमिस्त्री सुबोध दास सकरी चीनी मिल स्थित एसबीआई शाखा से पांच लाख रुपये की निकासी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नेहरा लुल्ववा चौक के पास उन्होंने सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी की और पेशाब करने चले गए। इसी बीच बैंक से ही उनका पीछा कर रहे चोरों ने मोटरसाइकिल की डिक्की से रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरी की गई पूरी राशि बरामद कर ली। न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को राशि उसके वास्तविक मालिक को लौटा दी गई। अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने पर सुबोध दास और उनके परिवर्जनों ने नेहरा थाना पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। राशि की बरामदगी और वापसी से परिवार को बड़ी राहत मिली है।

जदयू के नव मनोजीत पदाधिकारियों का किया सम्मान



अररिया। फारबिसगंज के एक होटल के सभागार में बुधवार को जदयू की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर नव मनोजीत पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर बिर्द्रे कुमार राय को पुनः दोबारा अररिया जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष के रूप में मनोजीत किया गया।जबकि लंबे समय से संगठन हित में काम कर रहे सीताराम मंडल को पुनः दूसरी बार और महेंद्र सिंह चौहान को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विकसित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल एवं जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी सौंपी है, उस पर खरा उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संगठन को प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। समारोह में मुख्य रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, प्रदेश सचिव संचिता मंडल, पूर्व प्रदेश सचिव रमेश सिंह, शिक्षा मंत्री प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नितेश कुमार राय,अमृता कुमारी, नरपतंगज प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण राय, मिथिलेश ऋषि देव, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष उमेश पासवान, वकील सिंह यादव, गुड्डू अली, तेज नारायण यादव, जिला महासचिव जावेद अंसारी, अफरोज आलम, संजय कामत, अजय मंडल, संजय मेहता, अनंत राय के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए।

कटिहार में ट्रैफिक नियम तोड़े तो ठीली होगी जेब: एक ही दिन में 262 चालान, 10 लाख से अधिक जुर्माना

कटिहार। जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के कड़े अनुपालन को लेकर परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को जिले में 262 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान विभिन्न नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से कुल 10,04,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग की टीम ने महिला थाना के समीप और सिरसा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान विशेष रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने, गलत दिशा (रैंग नाइड) में ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के मामलों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्री बसों के परमिट व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई, साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और बिना पंजीकरण सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा (टोटो) व ऑटो को भी जब्त कर जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दायरे में वाहन विक्रेताओं को भी लिया गया है। विभाग ने नए वाहनों के पंजीकरण में अनावश्यक देरी करने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों और शोरूम संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है। स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीकरण के सड़क पर वाहन चलते पाए जाने की स्थिति में चालक के साथ-साथ संबंधित डीलर के विरुद्ध भी कानूनी जवाबदेही तय की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान सभी अनिवार्य दस्तावेज साथ रखें, दोपहिया पर हेलमेट व कार में सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करें और किसी भी स्थिति में नाबालिगों को वाहन न सौंपें। विभागीय जानकारी के अनुसार यह विशेष जांच अभियान 20 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इसके बाद भी जिले के विभिन्न संवेदनशील मार्गों पर नियमित औचक जांच जारी रहेगी। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व वसूली के साथ-साथ सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और आम नागरिकों को सुरक्षित सफ़र के प्रति जागरूक करना है।

नाव दुर्घटना पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा मिले, नावों की सुरक्षा और बांध-पुल निर्माण की हो उच्चस्तरीय जांच: पप्पू यादव

पटना,एजेंसी। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को पटना में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न जनसमस्याओं से जुड़ा ज्ञान सौंपा। उन्होंने राघोपुर में बाढ़ और नाव दुर्घटनाओं में हुई मौतों पर चिंता जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 10–10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। इसके साथ ही नावों की सुरक्षा, बांध और पुल निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच, युवाओं की नियुक्ति, शिक्षा व्यवस्था, स्थानीय निवास नीति और महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर कार्रवाई का आग्रह किया।

पप्पू यादव ने कहा कि भागलपुर में नाव दुर्घटना के अलावा छपरा के मकरे, परसा, अमनौर और पानापुर जैसे इलाकों में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों को जान जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने छपरा में करीब 40 से 50 और बेतिया में करीब 18 लोगों की मौत की जानकारी का उल्लेख किया। उनके अनुसार, कई लोगों की मौत नाव पलटने, डूबने और सांप काटने से हुई है, लेकिन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने हाल में नाव दुर्घटना में 14 बच्चों की मौत को बेहद दुःखद बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि नावों में लाइफ जैकेट और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। रात में असुरक्षित तरीके से नावों का परिचालन नहीं होना चाहिए। उन्होंने दीपावली और छठ तक जल परिवहन की व्यवस्था बनाए रखने, कम से कम 40 स्टीमर चलाने तथा भागलपुर के विक्रमशिला गंगा तटवर्ती क्षेत्र में बड़ी यात्री नावों और ट्रैक्टरों की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने गंडक नदी के तटबंधों के टूटने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में

लालबाग के राष्ट्रीय विद्यालय को संरक्षित स्मारक बनाने की कवायद तेज

दरभंगा। दरभंगा शहर के लालबाग स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रीय विद्यालय को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कराने की दिशा में पहल तेज हो गई है। स्थानीय सांसद सहज हो लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपालजी ठाकुर की पहल पर जिला प्रशासन ने स्थल निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, जीर्णोद्धार और पर्यटन की दृष्टि से विकास करना है।

सांसद डॉ. ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय विद्यालय के संरक्षण के लिए उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, बिहार के मुख्यमंत्री तथा पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था। इसके बाद बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के पुरातत्व निदेशालय के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन राष्ट्रीय विद्यालय की भूमि के मौजा, खाता, खेसरा, रकबा और संभावित अतिक्रमण से संबंधित विस्तृत विवरण तैयार कर पुरातत्व निदेशालय को भेजेगा। इसके बाद भूमि का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने तथा विद्यालय भवन को संरक्षित

स्मारक घोषित कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। सांसद ने राष्ट्रीय विद्यालय को स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटनाओं और राष्ट्रसेवी स्वर्गीय कमलेश्वरी चरण सिन्हा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों से जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय केवल दरभंगा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मिथिला की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण और जीर्णोद्धार भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय विद्यालय को संरक्षित स्मारक का दर्जा मिलने से इसकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। डॉ. ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय विद्यालय सहित दरभंगा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने राजकिला, शहर के तीनों ऐतिहासिक तालाबों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा मिथिला की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

राघोपुरदियारा नाव हादसा : केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पीड़ित परिवारों से मिलकर जताई संवेदना, मुआवजे की घोषणा

पटना,एजेंसी। राघोपुर दियारा में हुए नाव हादसे में मासूम बच्चों समेत 13 लोगों की मौत पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दुःख की घड़ी में हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। केंद्र और राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद के लिए तत्पर हैं।

हादसे में 13 मृतकों और सात घायलों के लिए घोषित मुआवजे का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये और घायल को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। हादसे के बाद नावों की सुरक्षा को लेकर भी नित्यानंद राय ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने वैशाली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि टूटी, खराब या क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत सुनिश्चित करने के बाद ही उनका नदी में परिचालन कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नावों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा से भी इस मामले में बात की। उन्होंने जर्जर और क्षतिग्रस्त



कथित लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने और नारायणी नदी से मुजफ्फरपुर तथा आसपास के इलाकों में संभावित नुकसान को लेकर भी चिंता जताई। पप्पू यादव ने कहा कि बांध टूटने के मामलों में केवल इंजीनियरों को निर्लखित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। टूटे पुलों में इस्तेमाल सरिया की गुणवत्ता, मेसर्स श्याम स्टील की सरिया और निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के पालन की जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल टीएमटी सरिया, विभागों की अनुमोदित मेक सूची और बिलो रेट पर आवंटित निविदाओं की भी जांच कराने को कहा। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सांसद ने बिहार के नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने और दर्शनशास्त्र विभाग की स्थापना की मांग की। उन्होंने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति

मदरिया के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की पिटाई, छात्रा से दुर्व्यवहार के आरोप से बड़ा विवाद

दरभंगा,एजेंसी। दरभंगा जिले के तारडीह

प्रखंड अंतर्गत बैका पंचायत के मदरिया गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर विवाद को लेकर चर्चा में है। गत मंगलवार को विद्यालय परिसर में रामकुमार नामक शिक्षक के साथ करीब दर्जन भर महिलाओं द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। महिलाओं ने शिक्षक पर पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं, शिक्षक ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और झूठ बताया है।

ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित छात्रा ने अपनी मां को विद्यालय में शिक्षक द्वारा कथित दुर्व्यवहार किए जाने की बात बताई थी। इसके बाद आक्रोशित महिलाएं विद्यालय पहुंचीं और शिक्षक के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान झाड़ू-चप्पल के अलावा हाथ, लात और घूंसे से भी उनकी पिटाई की गई। हालांकि, छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रामकुमार शिक्षक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निरे से खारिज किया है। दूसरी ओर, विद्यालय के कुछ शिक्षक उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच भी घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जबकि कुछ ग्रामीण शिक्षक के साथ मारपीट किए जाने और उसके

सोनहद में जमीन विवाद के बीच जान से मारने की धमकी का आरोप, ग्रामीणों ने मांगी सुरक्षा

दरभंगा। जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कोर्थु पंचायत अंतर्गत सोनहद गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने का मामला सामने आया है। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों को सार्वजनिक रूप से काट देने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ से मामला आगे बढ़ने से बच गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार, जमीन विवाद के दौरान कथित तौर पर एक ब्राह्मण व्यक्ति को खुलेआम काट देने की धमकी दी गई। इस घटनाक्रम ने गांव के लोगों को चिंतित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन संबंधी विवाद अपनी जगह है, लेकिन किसी को धमकाना या कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे मामलों में समय रहते प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि विवाद गंभीर रूप न ले सके। घटना के मद्देनजर ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने प्रशासन से मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने, कथित रूप से धमकी का सामना कर रहे व्यक्ति और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने

की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी जमीन विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए। धमकी और भय के माहौल में लोगों का रहना सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है। प्रशासन को मामले का सज्ञान लेकर गांव में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ग्रामीणों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर कुश्रेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में पूर्व में हुई घटना की भी चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि विवाद को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, तो स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि, सोनहद की घटना और हरिनगर की घटना का बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित आवेदन नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

ऐसे में घटना के संबंध में पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई और पक्षों के बयान सामने आना बाकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले को केवल जमीन विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाए, बल्कि लगाए गए धमकी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।



कि यदि किसी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि शिक्षक निर्दोष हैं, तो उनके साथ मारपीट करने वालों पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत के आधार पर कानून को अपने हाथ में लेना उचित नहीं है।

ऐसी घटनाओं से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित होता है और गांव की शैक्षणिक व्यवस्था की छवि भी धूमिल होती है। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बताया जाता है कि घटना के संबंध में अब तक दोनों पक्षों में से किसी ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है। इसी कारण पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं होने की बात सामने आ रही है। विद्यालय के शिक्षक नारायण झा और कमलापति मिश्र ने भी रामकुमार को कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी, लेकिन शिक्षक ने फिलहाल इस दिशा में कदम नहीं उठाया है। हालांकि, शिक्षक द्वारा शिकायत नहीं किए जाने को उनके विरुद्ध आरोपों का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, छात्रा की शिकायत की गंभीरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मदरिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई इस घटना ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्रा के आरोपों की विधिवत जांच होगी? क्या शिक्षक के साथ मारपीट करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी? और क्या प्रशासन विद्यालय में भ्रममुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पहल करेगा?

यात्रा से परिष्कृत होता है अनुभव, समृद्ध होता है साहित्य : प्रो. विजय कुमार

दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में चित्र-यात्रा प्रदर्शनी के साथ 'यात्रा-वृत्तांत' विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय की मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. पुनीता झा ने किया। प्रदर्शनी का संयोजन हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. एके बच्चन एवं राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. मुनेश्वर यादव ने प्रदर्शनी की सराहना की। प्रदर्शनी में वर्ष 2024 से 2026 के बीच विभागीय शोधार्थियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा बिहार, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्राओं के दौरान लिए गए चित्र प्रदर्शित किए गए। इनमें राजनगर, मधुबनी, लेकिन दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता सहित हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया।

साथ उसके साहित्यिक अनुभवों को भी समृद्ध करती है। ऐसी प्रदर्शनियां शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय की मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. पुनीता झा ने किया। प्रदर्शनी का संयोजन हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. एके बच्चन एवं राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. मुनेश्वर यादव ने प्रदर्शनी की सराहना की। प्रदर्शनी में वर्ष 2024 से 2026 के बीच विभागीय शोधार्थियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा बिहार, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्राओं के दौरान लिए गए चित्र प्रदर्शित किए गए। इनमें राजनगर, मधुबनी, लेकिन दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता सहित हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया।

साथ उसके साहित्यिक अनुभवों को भी समृद्ध करती है। ऐसी प्रदर्शनियां शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. विजय कुमार ने कहा कि यात्रा-वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अनेक साहित्यकारों ने इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश और जीवनशैली से पाठकों को परिचित कराया है। यात्रा से मनुष्य के अनुभव परिष्कृत होते हैं और उसकी दृष्टि व्यापक बनती है। प्रो. उमेश कुमार ने कहा कि यात्रा साहित्य और कला-सृजन को नई प्रेरणा देती है तथा अनुभूतियों को प्रगाढ़ बनाती है। हिंदी में यात्रा-वृत्तांत लेखन की परंपरा भारतेन्दु युग से विकसित हुई। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन जैसे साहित्यकारों के लेखन में घुमक्कड़ी और यात्रा-अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. मंजरी खरे ने कहा कि यात्रा जीवन को नया अर्थ देने के साथ अनुभूतियों को नए आयाम प्रदान करती है। वहीं, डॉ. बिंदु चौहान ने प्रकृति और संस्कृति से जुड़ी ऐसी प्रदर्शनियों को प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बताया। कार्यक्रम में मलय नीरव, सुभद्रा कुमारी, कंचन रजक, जय प्रकाश, रोहित पटेल, स्नेहा कुमारी, बेबी कुमारी, सुफिया खातून, अपर्णा, धीरज, सूरज, सदानंद, प्रतिभा, मनीष सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

एक नजर

युवराज ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए तय किया लक्ष्य, बोले – ‘ हम चैंपियन बनने आए हैं’



नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 में ‘ दिल्ली कैपिटल्स को चैंपियन बनाने का लक्ष्य रखा है। टीम के सहायक और बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालने जा रहे युवराज ने कहा कि उनका उद्देश्य खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाना, दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना और टीम में जीत की संस्कृति विकसित करना है। आईपीएल में पहली बार औपचारिक कोचिंग की भूमिका निभाने जा रहे युवराज दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच सीरव गांगुली के साथ काम करेंगे। युवराज ने गांगुली की कप्तानी में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। अब दोनों एक बार फिर भारतीय क्रिकेट की इस चर्चित जोड़ी के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। युवराज ने बताया कि गांगुली ने उनसे सहायक की भूमिका निभाने के बारे में पूछा था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से गांगुली के सहायक की तरह ही काम करते आ रहे हैं। युवराज के मुताबिक, वह पिछले तीन-चार वर्षों से इस अवसर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ियों के साथ काम किया, लेकिन पूरी टीम के साथ जुड़ना उनके लिए नया अनुभव होगा। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि गांगुली से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूत टीम वातावरण तैयार करना सीखा है। उनके अनुसार, गांगुली ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एकजुट रखा और उनमें विदेश में भी दुर्गमिंत जीतने का विश्वास पैदा किया। युवराज ने उन्हें बड़े भाई जैसा बताते हुए कहा कि वह उनके अनुभव से सीखने के साथ अपने विचार भी साझा करना चाहते हैं।

सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप : हरियाणा, अरुणांचल और महाराष्ट्र ने जीते मुकाबले



झांसी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप-2026 में बुधवार को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। हॉकी इंडिया, नई दिल्ली के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हॉकी, जिला प्रशासन झांसी और क्षेत्रीय खेल कार्यालय के संयुक्त समन्वय से आयोजित प्रतियोगिता में पांच मैच खेले गए। पहले मुकाबले में हॉकी हरियाणा ने दिल्ली हॉकी को 3–1 गोल से शिकस्त दी। हरियाणा की ओर से जर्सी नंबर–10 जोगिंदर सिंह, जर्सी नंबर–21 दीपक और जर्सी नंबर–49 मंजीत ने एक–एक गोल किया। दूसरे मुकाबले में हॉकी अरुणांचल ने हॉकी झारखंड को 2–1 से हराया। अरुणांचल के कप्तान अभिनव सिंह और सतीश यादव ने एक–एक गोल किया। हॉकी महाराष्ट्र और एलई पुडुचेरी हॉकी के बीच मुकाबला भी रोमांचक रहा। महाराष्ट्र ने 2–1 से जीत दर्ज की। विजेता टीम की ओर से गणेश पाटिल और दर्शन विभव गावकर ने एक–एक गोल किया। चौथे मुकाबले में केरल हॉकी ने असम हॉकी को 5–2 गोल से पराजित किया। दिन का अंतिम मुकाबला हॉकी यूनित ऑफ तमिलनाडू और हॉकी बंगाल के बीच हुआ, जो 1–1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। तमिलनाडू की ओर से शानमुगम पी और बंगाल की ओर से सुनीत लिकरा ने गोल किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉ. अनुराग शीवास्तव और विशिष्ट अतिथि इंजीनियर रविकांत दुबे मौजूद रहे। हॉकी इंडिया के चयनकर्ता एवं ओलंपियन बलविंदर सिंह शम्मी और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के चयनकर्ता/कोच फ्रेडरिक सोयेज भी उपस्थित रहे। 15 अक्टूबर को यूपी हॉकी और हॉकी चंडीगढ़ के बीच शाम पांच बजे मुकाबला होगा। इसके अलावा हॉकी पंजाब–बंगाल, मध्य प्रदेश–पुडुचेरी और मणिपुर–दिल्ली समेत अन्य मुकाबले भी खेले जाएंगे।

ओपी जिंदल क्रिकेट एकेडमी के राहुल प्रधान का रणजी ट्रॉफी में चयन

रायगढ़। सौराष्ट्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ की ओर से खेल रहे राहुल ने रिविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाजों का किया सामना, सक्षम चौबे का वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए चयनओपी जिंदल क्रिकेट एकेडमी, घरघोड़ा से प्रशिक्षण प्राप्त राहुल प्रधान का चयन छत्तीसगढ़ की रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ है। गुजरात में सौराष्ट्र के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 41 रन बनाए। वहीं, एकेडमी के एक अन्य खिलाड़ी सक्षम चौबे का चयन वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि रायगढ़ जिले के लिए गौरव का विषय है। जिंदल पावर, तमनार द्वारा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिंदल फाउंडेशन द्वारा घरघोड़ा में ओपी जिंदल क्रिकेट एकेडमी का संचालन किया जा रहा है। यहां खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां का प्रशिक्षण देकर उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। अब एकेडमी के खिलाड़ियों की उपलब्धियां इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने ला रही हैं। छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन राहुल प्रधान को बल्लेबाजी का अवसर मिला।

41 हजार से अधिक धावक दौड़ेंगे दिल्ली हाफ मैराथन में, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

नई दिल्ली,एजेंसी। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में 41 हजार से अधिक प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। रविवार, 18 अक्टूबर को होने वाली इस विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रोड रेस के लिए आयोजक प्रोकेम इंटरनेशनल ने सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, यातायात और पर्यावरण प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की हैं। दौड़ में मैदान पर उतरने वाले प्रतिभागियों के साथ वरचुअल श्रेणी में शामिल धावक भी हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार, धावकों की सुरक्षा और उन्हें सुचारु अनुभव उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे रूट और फिनिश लाइन पर सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के साथ पिछले डेढ़ महीने से तैयारियां चल रही हैं। आयोजन के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मियों और 70 से 80 यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

आयोजन की तैयारियों के तहत हाफ मैराथन और ओपन 10 किलोमीटर दौड़ के मार्ग में कुछ बदलाव किए गए हैं। ओपन 10 किलोमीटर दौड़ अब संसद मार्ग के बजाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सुबह 7:35 बजे शुरू होगी। सभी दौड़ें इसी स्टेडियम से शुरू होकर वहीं समाप्त होंगी। प्रोकेम इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने कहा कि दिल्ली हाफ मैराथन का प्रभाव खेल तक सीमित नहीं है। मिरांडा हाउस के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव अध्ययन के अनुसार, आयोजन का दिल्ली–एनसीआर पर 400 करोड़ रुपये से अधिक का प्रभाव पड़ा है। देशभर से आने वाले धावकों और उनके परिजनों से स्थानीय



कारोबार, होटल, आतिथ्य और खुदरा क्षेत्र को भी लाभ मिलाता है। धावकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की ओर से व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की गई है। पूरे रूट पर 11 मेडिकल स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि फिनिश लाइन के बाद आईसीयू सुविधा से युक्त मेडिकल बेस कैंप रहेगा। होल्डिंग एरिया में दो और रिफ्रेशमेंट क्षेत्र के बाद एक चिकित्सा स्टेशन होगा। आयोजन में कुल 450 चिकित्सा कर्मियों, 25 मेडिकल स्पॉटर और बाइक पर तैनात नौ चिकित्सा कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। आपात स्थितियों से निपटने के लिए 12 एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) एंबुलेंस और तीन गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध रहेंगे। सह–चिकित्सा निदेशक डॉ.

समीर गुप्ता ने कहा कि 41 हजार से अधिक धावकों की भागीदारी को देखते हुए चिकित्सा टीमों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उनका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर प्रतिभागियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है। धावकों को दौड़ के दौरान तरोताजा रखने के लिए रूट पर पानी और जलयोजन की सुविधाएं रहेंगी। आयोजकों के मुताबिक, बिसलेरी की ओर से वाटर स्टेशन, री-हाइड्रेशन स्टेशन और मिस्ट जोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा संतरे और नमक, चिक्की तथा अन्य सहायता केंद्रों की व्यवस्था होगी। धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आठ चीयरिंग जोन और 12 प्रेरणा जोन भी बनाए जाएंगे। इनमें संगीत, बैंड और विभिन्न समूहों की गतिविधियां शामिल होंगी।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग : टीमों की अगुवाई करेंगे हॉकी ओलंपियन्स

रायपुर। रायपुर में होने वाले छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के मुख्य प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से खेल चुके प्रतिष्ठित और अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों को प्रत्येक टीम में (मार्की) खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है।

शासन द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार लीग में खेलने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों के सानिध्य में राज्य के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में टीमें खिताब के लिए दावेदारी करेंगी। इस दौरान नामी प्रशिक्षकों से राज्य के खिलाड़ियों को हॉकी के गुर सीखने के साथ ही बड़े मुकाबलों के दबाव से निपटने की कला भी सीखने मिलेगी। प्रतियोगिता के सभी मुकाबलों का विधिवत आयोजन हॉकी इंडिया के ऑफिशियल्स और अधिकारी करेंगे। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की टीमों में राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों, ओलंपियनों, स्थानीय प्रतिभाओं और छत्तीसगढ़ के अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। लीग में राज्य की प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय मंच मिलने के साथ ही

घरेलू हॉकी के ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। लीग के सभी मैच 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर के बीच रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम साढ़े पांच बजे और दूसरा मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।

दोनों मैचों के बीच प्रतिदिन मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। लीग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की छह फ्रेंचाइजी टीमों के साथ प्रतिष्ठित संस्थान जुड़े हैं। चक्रधर चैंपियंस की फ्रेंचाइजी जिंदल स्टील लिमिटेड , न्यायधानी नाइट्स की साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , राजधानी रॉयल्स की श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड , मैनपाट टाइगर्स की छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स की सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड और बैलाडीला बुल्स की फ्रेंचाइजी एनएमडीसी लिमिटेड के पास है।

आदित्य के बहुमुखी प्रदर्शन से इलाहाबाद पश्चिम सेमीफाइनल में, उतरी की रोमांचक जीत

प्रयागराज। नीलम करवरिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में बुधवार को इलाहाबाद पश्चिम ने इलाहाबाद दक्षिण को आठ विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं, दूसरे मुकाबले में इलाहाबाद उत्तरी ने रोमांचक संघर्ष में कोरांव विधानसभा को महज एक रन से पराजित किया। इलाहाबाद पश्चिम की जीत में आदित्य राज तिवारी और सागर शर्मा ने अहम भूमिका निभाई, जबकि इलाहाबाद उत्तरी की जीत के नायक राहुल राज पाल रहे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए। केपी कॉलेज मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इलाहाबाद दक्षिण की टीम 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। टीम की ओर से निशांत कुदियावा ने 41 रन बनाए, जबकि अक्षत पांडेय और अमर काला ने 16–16 रनों का योगदान दिया। इलाहाबाद पश्चिम की ओर से देव प्रकाश शुक्ला ने दो विकेट लिए। आदित्य राज तिवारी और आतिफ साजिद ने भी दो–दो खिलाड़ियों को आउट किया।

112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इलाहाबाद पश्चिम की टीम ने 16.1 ओवर में दो विकेट खोकर 112 रन बनाते हुए मुकाबला जीत लिया। सागर शर्मा ने 49 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। वहीं, आदित्य राज तिवारी ने 38 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों की सहायता से 44 रन की पारी



खेली। गेंदबाजी में अमर काला और अक्षत पांडेय को एक–एक विकेट मिला। आदित्य राज तिवारी को उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच से पहले गौरव करवरिया और सोमेश्वर पांडेय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पुरस्कार पूर्व खिलाड़ी रजा अली ने प्रदान किया। दिन के दूसरे मुकाबले में इलाहाबाद उत्तरी ने कोरांव विधानसभा को एक रन से हराकर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इलाहाबाद उत्तरी ने निर्धारित 20 ओवर में 139 रन बनाए। राहुल राज पाल ने 68 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 91 रन की शानदार पारी खेली। अंशुमान पांडेय ने 17 रन बनाए। कोरांव की ओर से

अनंत कुमार गुप्ता और श्याम सुंदर ने दो–दो विकेट लिए, जबकि कृणाल मिश्र को एक संफलता मिली। 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोरांव विधानसभा की टीम 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। शाश्वत प्रताप ने 52, अंशुराग यादव ने 34 और सचिन ओझा ने 23 रन बनाए, लेकिन टीम जीत से एक रन दूर रह गई। इलाहाबाद उत्तरी की ओर से सुब्रत प्रसाद तिवारी ने दो विकेट लिए, जबकि प्रथम मिश्र और अंशुमान पांडेय को एक–एक विकेट मिला। 91 रन की शानदार पारी खेलने वाले राहुल राज पाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच से पहले गरीब दास ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पुरस्कार पूर्व ईस्ट जोन खिलाड़ी फरासत अली ने प्रदान किया।

विजयवाड़ा, एजेंसी। कर्नाटक के अनुभवी

बल्लेबाज करुण नायर ने आंध्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहली पारी की नाकामी से उबरते हुए शानदार शतक जड़ा। बुधवार को पहली पारी में केवल आठ रन बनाने वाले 34 वर्षीय नायर ने दूसरी पारी में दमदार बल्लेबाजी करते हुए राणजी ट्रॉफी में अपना 20वां शतक पूरा किया। नायर ने अपनी लय हासिल करते हुए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सौरभ और ललित मोहन के खिलाफ शानदार छक्के लगाए। उन्होंने गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाकर अपने आक्रामक अंदाज की झलक दिखाई। पहली पारी में कम स्कोर के बाद उनका यह शतक उनकी बल्लेबाजी क्षमता का प्रभावशाली उदाहरण रहा।

नायर के लिए पिछले कुछ महीने उतार–चढ़ाव भरे रहे हैं। उन्हें 2026 की दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल, दोनों मुकाबलों के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद वह बेंगलुरु लोटे और रणजी ट्रॉफी सत्र की तैयारी के लिए कर्नाटक के पारंपरिक लाल गेंद वाले दुर्गमिंत थिम्मप्पैया ट्रॉफी में केएससीए सचिव एकादश की ओर से खेले। आंध्र के खिलाफ आया यह शतक उनके लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने की कोशिश में एक अहम कदम है। वह पिछले साल भारतीय टेस्ट टीम में शानदार बल्लेबाजी के बाद अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नायर ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने यह श्रृंखला 2–2 से बराबर की थी। कुछ महीने पहले



तक मुश्किल नजर आ रही उनकी वापसी घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का नतीजा थी। 2024–25 सत्र में विदर्भ की ओर से खेलते हुए नायर ने रणजी ट्रॉफी में 863 रन बनाए थे। इस दौरान उनका औसत 53.93 रहा और विदर्भ ने खिताब जीता। विजय हजारें ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। उन्होंने आठ पारियों में पांच शतक लगाए और 389.50 के असाधारण औसत से रन बनाए। घरेलू क्रिकेट में इन दमदार प्रदर्शनों ने चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा था और उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिला। आंध्र के खिलाफ ताजा शतक से नायर ने एक बार फिर साबित किया है कि बड़े स्कोर बनाने की उनकी भूख अब भी बरकरार है। मैच की बात करें तो इस मुकाबले में कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान समरन

रविचंद्रन (126) के शानदार शतक और कृष्णन श्रीजीत के (58) के अर्धशतक की बदौलत 274 रन बनाए। जिसके जवाब में आंध्र प्रदेश ने सीरम वेंकट राहुल (119) के शतक और रेवंथ रेड्डी (97), शेख रशीद (54) के अर्धशतकों की बदौलत अपनी पहली पारी में 418 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 144 रन की बढ़त हासिल की। कर्नाटका ने दूसरी पारी में करुण नायर के नाबाद 155 रनों की शतकीय पारी की बदौलत 9 विकेट पर 337 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और आंध्र प्रदेश के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा। समाचार लिखे जाने तक आंध्रा ने 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में केवल 43 रन पर 3 विकेट खो दिये हैं और उसे जीतने के लिए अभी भी 151 रनों की आवश्यकता है, जबकि 28 ओवर शेष है।

गांगुली, रहाणे, लारा और रूट ने प्रिंस विलियम के साथ खेला टेनिस बॉल क्रिकेट, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

लंदन। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और अजिंक्य रहाणे सहित क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने लंदन में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट का मैत्रीपूर्ण मुकाबला खेला। इस खास आयोजन का उद्देश्य क्रिकेट के प्रति भारत और ब्रिटेन के साझा जुनून का जश्न मनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यह आयोजन अगले महीने मुंबई में होने वाले अर्थशांति पुरस्कार समारोह की उलटी गिनती के तहत किया गया। द रॉयल फाउंडेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह मुकाबला बकिंघम पैलेस के बाहर स्थित द मॉल मार्ग पर खेला गया। इस ऐतिहासिक मार्ग का इस्तेमाल आमतौर पर शाही समारोहों और भव्य जुलूसों के लिए किया जाता है। आयोजन में वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा, इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रूक सहित कई प्रमुख क्रिकेट हस्तियां शामिल हुईं।

हाल ही में अपने शानदार क्रिकेट करियर को अलविदा कहने वाले रहाणे ने बुधवार को लिंकडइन पर एक पोस्ट के जरिए इस आयोजन का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि बकिंघम पैलेस की पृष्ठभूमि में लंदन के द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना उनके लिए लंबे समय तक याद रहने वाला अनुभव होगा। रहाणे ने लिखा, ‘क्रिकेट मुझे दुनिया भर के कुछ शानदार मैदानों तक ले गया है, लेकिन बकिंघम पैलेस की पृष्ठभूमि में लंदन के द मॉल पर टेनिस बॉल से क्रिकेट

वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, वीएफआई के महासचिव प्रमोद कुमार निलंबित

नई दिल्ली। भारतीय मुकदेबाजी महासंघ (वीएफआई) ने महासचिव प्रमोद कुमार को कथित तौर पर अधिकारों के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम निलंबन है और इसे आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा।

वीएफआई की ओर से जारी बयान के अनुसार महासंघ के संविधान की धारा 24 के उपखंड 16 और धारा 24 के उपखंड 36 के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रमोद कुमार पर अधिकारों के खुले दुरुपयोग, जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने, जांच में सक्रिय रूप से बाधा डालने और वित्तीय अनियमितताओं तथा अनुचित आचरण के अस्पष्ट मामलों के आरोप लगाए गए हैं। मंगलवार को जारी पत्र में प्रमोद कुमार पर हिमाचल प्रदेश के नाहन में 16 से 23 अगस्त तक प्रस्तावित बीएफआई एलीट पुरुष एवं महिला ओपन मुकदेबाजी चैंपियनशिप 2026 को रद्द किए जाने के मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि वह महासंघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं और उसकी प्रतिष्ठा पर असर डालने वाले गंभीर मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन पर स्वतंत्र जांच को डराने और बाधित करने के उद्देश्य से कथित तौर पर अवैध और दुर्भावनापूर्ण

नोटिस जारी करने का आरोप भी लगाया गया है। निलंबन आदेश के अनुसार जांच पूरी होने तक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश में बदलाव अथवा उसे रद्द किए जाने तक प्रमोद कुमार महासचिव के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। यह कार्रवाई वीएफआई के संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अधीन रहेगी। निलंबन की अवधि में प्रमोद कुमार महासंघ के महासचिव के रूप में किसी भी अधिकार, शक्ति या जिम्मेदारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें वीएफआई के नाम पर पत्राचार करने, नोटिस जारी करने या निर्देश देने से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें जांच समिति की कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने, गवाहों, अधिकारियों या जांच से जुड़े अन्य लोगों को प्रभावित करने के प्रयास से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें जांच समिति के साथ पूरा सहयोग करने और मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि निलंबन आदेश का उल्लंघन करने, जांच में बाधा डालने, वीएफआई के अधिकारों का दुरुपयोग करने या जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में महासंघ के संविधान और लागू नियमों के तहत आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एक नजर

इजराइल ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से 12 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का किया समझौता



तेल अबीव। इजराइल ने अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से 12 उन्नत अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस सौदे के तहत अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग इजराइली वायुसेना को एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगी। इनकी आपूर्ति 2030 के दशक की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने इस खरीद के लिए मंत्रालय को एक अरब शेकेल की राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत इजराइल को अपाचे हेलीकॉप्टरों का ‘इको’ संस्करण मिलेगा, जिसे इस हेलीकॉप्टर का सबसे नया और उन्नत मॉडल बताया गया है। इस खरीद का उद्देश्य इजराइली रक्षा बलों की परिचालन क्षमता को मजबूत करना और विभिन्न प्रकार के सुरक्षा खतरों से निपटने की तैयारी बढ़ाना है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस सौदे को देश की सैन्य क्षमता के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे इजराइली रक्षा बलों की परिचालन क्षमताएं मजबूत होंगी और आने वाले वर्षों में देश की सुरक्षा को लाभ मिलेगा। इजराइली वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार, अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद का फैसला सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद गाजा पट्टी में हुई लड़ाई से मिले अनुभवों और सबक के मद्देनजर लिया गया है।

नेटफिलक्स में छह प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती, 2022 के बाद सबसे बड़ी छंटनी



न्यूयॉर्क। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफिलक्स करीब छह प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से लगभग एक हजार कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी। वर्ष 2022 के बाद कंपनी में यह सबसे बड़ी छंटनी बताई जा रही है। रिपोर्ट में कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल के हवाले से बताया गया है कि कंपनी के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग पीटर्स और टेड सारंडोस ने बुधवार सुबह कर्मचारियों को इस फैसले की जानकारी दी। छंटनी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की प्रोडक्ट, प्रौद्योगिकी, कानूनी और मानव संसाधन (एचआर) टीमों पर पड़ने की संभावना है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। स्ट्रीमिंग सेवाओं के बढ़ते विकल्पों के बीच कंपनियां अपने कारोबार और खर्चों में बदलाव कर रही हैं। नेटफिलक्स की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वर्ष 2025 के अंत तक नेटफिलक्स में करीब 16,000 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी अब केवल सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई पर निर्भर रहने के बजाय विज्ञापन, लाइव कार्यक्रमों और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ा रही है, ताकि आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकें।

महिला को अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सांसद खगेन्द्र सुनार के खिलाफ जांच शुरू



काठमांडू। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद खगेन्द्र सुनार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने और उसे जान से मारने की धमकी देने से संबंधित ऑडियो सार्वजनिक होने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। बांके से निर्वाचित संघीय सांसद खगेन्द्र सुनार द्वारा कथित तौर पर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आने वाली धमकी दिए जाने के बाद आरएसपी ने आंतरिक जांच शुरू की है। इतना ही नहीं सांसद सुनार पर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सहभागी होने पर पार्टी ने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी के महामंत्री विपिन कुमार आचार्य ने बुधवार सुबह जारी एक बयान में कहा कि सार्वजनिक हुए इन मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि राज्य के संबंधित निकाय तत्काल स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच करेंगे। उनहोने बताया कि इस मामले में सरकार में शामिल पदाधिकारियों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही है। यह ऑडियो को एक स्थानीय मीडिया ने सार्वजनिक किया था। ऑडियो में कथित तौर पर एक महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए समय पर पैसे नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई है। सुनार सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय सदस्य भी हैं।

यूएनएचआरसी में तीसरी बार सदस्य चुना गया नेपाल, 180 में से मिले 173 वोट

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के वर्ष 2027–2029 के कार्यकाल के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए चुनाव में नेपाल को महासभा में पड़े कुल 180 मतों में से 173 मत मिले। एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह से निर्वाचित देशों में नेपाल को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए। चुनाव के बाद न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी मिशन ने एक बयान जारी कर नेपाल को विश्वास और समर्थन देने वाले संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मिशन ने कहा, ‘बहुपक्षवाद, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखने वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता पर विश्वास जताने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नेपाल ने मानवाधिकार परिषद के नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित अन्य देशों को भी बधाई दी है। इनमें ब्राजील, बुरुंडी, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, घाना, आयरलैंड, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोल्दोवा, नाइजीरिया, यूक्रेन, उरुग्वे और जाम्बिया शामिल हैं। नेपाल के स्थायी मिशन ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अन्य साझेदारों के साथ निकट सहयोग करते हुए मानव गरिमा की रक्षा, समावेशिता को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए समान और न्यायसंगत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल इससे पहले वर्ष 2018–2020 और 2021–2023 के दौरान



लगातार दो कार्यकाल तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है। नए चुनाव के साथ नेपाल 1 जनवरी 2027 से तीसरी बार परिषद का सदस्य बनेगा। वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। परिषद में भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित करती है। परिषद सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करती है, मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों पर चर्चा करती है और आवश्यक सिफारिशें जारी करती है। इसके अलावा, यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को

प्रोत्साहित करती है। परिषद की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के तहत सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन भी किया जाता है। नेपाल का निर्वाचन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंच पर देश का प्रतिनिधित्व मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। परिषद के सदस्य के रूप में नेपाल मानवाधिकार, मानव गरिमा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर बहुपक्षीय संवाद और सहयोग में योगदान दे सकेगा। हालांकि, सदस्यता के साथ नेपाल पर मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने, मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहार में उतारने की जिम्मेदारी भी होगी।

सऊदी अरब का यमन में बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों के फ्यूल डिपो को बनाया निशाना

रियाद। सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। सऊदी अरब ने मंगलवार को उत्तरी यमन में हूती विद्रोहियों के कथित इस्तेमाल वाले एक प्रमुख फ्यूल डिपो पर हमला किया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक, इस ठिकाने का इस्तेमाल सऊदी अरब के हवाई अड्डों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और लाल सागर में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने वाले अभियानों के लिए किया जा रहा था। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद और दक्षिणी क्षेत्रों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ रहा था।

दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष ने क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसकी सेना ने उत्तरी यमन स्थित अल-सबाहा सेंट्रल स्टेशन को निशाना बनाया। इसे हूती-निर्यात क्षेत्र के प्रमुख ईंधन वितरण केंद्रों में से एक बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्टेशन की भंडारण क्षमता लगभग 58,000 मीट्रिक टन है। गठबंधन का दावा है कि हूती विद्रोही

इस सुविधा का इस्तेमाल सैन्य अभियानों में सहायता के लिए कर रहे थे। इन अभियानों में सऊदी अरब के भीतर स्थित ठिकानों और लाल सागर के समुद्री मार्गों को निशाना बनाना शामिल था। हालांकि, हूती-निर्यात यमन अलाविक कंपनी ने इससे पहले कहा था कि इस केंद्र में पेट्रोलियम उत्पादों का कोई भंडार मौजूद नहीं था। कंपनी के मुताबिक, हमले से ईंधन के भंडार या आपूर्ति पर कोई बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं थी। हूती पक्ष के अनुसार, सऊदी हमले में दो आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। दूसरी ओर, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि कार्रवाई से पहले नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी गई थी। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुकी अल-मलिकी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य उन क्षमताओं को कमजोर करना था, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही सऊदी अरब, यमन, दक्षिणी लाल सागर और समुद्री मार्गों के लिए खतरा पैदा करने में करते हैं। हालांकि, हमले में हुए नुकसान और नागरिकों के हताहत होने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कजान सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई भारत के छह ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की किताबें, रूसी भाषा में किया गया अनुवाद

कजान,एजेंसी। कजान में होने वाले दो दिवसीय टाइम बिजनेस फोरम से पहले बुधवार को सेंट्रल लाइब्रेरी में भारतीय लेखकों की छह किताबों को शामिल किया। सभी किताबें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं द्वारा लिखी गई हैं जिनमें अमृता प्रीतम, गुलज़ार, फिराक गोरखपुरी, महाश्वेता देवी शामिल हैं। कजान के सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित इस खास मौके पर भारत के कॉन्सुलेट जनरल जय सुंदर, वाणी प्रकाशक के चेयरमैन अरुण माहेश्वरी, रिपब्लिक ऑफ तारतरस्तान के संस्कृति मंत्री इरादा अयुपोवा के साथ इन किताबों के अनुवाद मौजूद रहे।

इस मौके पर कजान में भारत के कॉन्सुलेट जनरल जय सुंदर ने कहा कि कला संस्कृति को साझे रूप से आगे बढ़ाने के लिए शब्द बेहद कारगर साबित होते हैं। इसी वजह से टाइम बिजनेस फोरम की शुरुवात से पहले आज भारत की छह प्रसिद्ध किताबों का रूसी भाषा में अनुवादित संस्करण यहां शामिल किया गया है। इससे रूस के लोग भी भारत की जीवन संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। जयसुंदर ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत और रूस के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरे रूसी-भारतीय व्यापार मंच ‘टाइम बिजनेस फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर विकसित करने के साथ तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, रक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।



इस मौके पर वाणी प्रकाशन के चेयरमैन अरुण माहेश्वरी ने हिन्दुस्थान समाचार के साथ खास बात चीत में बताया कि 1960 से अब तक रूसी साहित्य को भारत के लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, अब हमारा मकसद है कि रूस के लोग भी भारत के साहित्य को जाने। इस मकसद से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखकों की भारत के अलग भाषाओं से ली गई हैं जिसमें हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला भाषा शामिल है। इन सभी किताबों को रूसी भाषा में अनुवादित किया गया

है। वाणी प्रकाशन की सम्पादक अदिति माहेश्वरी ने बताया कि भारत का पुस्तक प्रकाशन उद्योग दुनिया में नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। नीलसन बुक स्कैन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का बुक पब्लिशिंग मार्केट 2030-31 तक 21.4 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा। यानी भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशन बाजार बन जाएगा।

ग्रीस की सरकार गिराने की धमकी का आरोप, ट्रंप ने राजदूत किम्बरली गिल्फॉयल को हटाया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने ग्रीस में अमेरिकी राजदूत किम्बरली गिल्फॉयल को पद से हटाने का फैसला किया है। गिल्फॉयल पर एक रिपब्लिकन डोनर से कथित तौर पर एक लाख डॉलर मांगने, अमेरिकी प्रशासन तक पहुंच दिलाने का वादा करने और अमेरिकी लिक्विडाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की खरीद को लेकर ग्रीस की सरकार पर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, गिल्फॉयल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को झुठा बताते हुए अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करने की बात कही है। रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार की सरकार पर दबाव बनाने के आरोपों के मुताबिक, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केटी ज़कारिया ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि प्रशासन ने गिल्फॉयल से इस्तीफा देने के लिए कहा है। इसके कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजदूत अच्छे काम कर रही थीं, लेकिन उनके बारे में सामने आई खबरें प्रशासन को पसंद नहीं आईं।

किम्बरली गिल्फॉयल ने पिछले साल सितंबर में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली थी। वह पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से सगाई को लेकर भी चर्चा में रही थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, गिल्फॉयल पर अपने राजनयिक पद का इस्तेमाल ग्रीस के ऊर्जा कारोबारी एलेक्जेंड्रोस एक्सार्चू के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने बाल्कन क्षेत्र की कई सरकारों पर एक्सार्चू के एक्वोर ग्रुप



में सुनिश्चित एकल और साझा अधिकारों को नौ वर्ष बीत जाने के बावजूद संघीय सरकार ने प्रदेशों को हस्तांतरित नहीं किया है। इसके कारण प्रदेश सरकारें जनाता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जैसे एकल अधिकार भी अब तक प्रदेशों को नहीं सौंपे गए हैं। वहीं, संघीय सरकार की ओर से आवश्यक कानून नहीं बनाए जाने के कारण शिक्षा,

स्वास्थ्य, निजामती कर्मचारी सेवा और वन सहित कई क्षेत्रों से जुड़े कानूनों को लागू करने में भी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि संघीय सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश सीमित संसाधनों के चलते संघीय अनुदान पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद वित्तीय संघीयता को लागू करने की दिशा में संघीय सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।

संघीयता के अभाव में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत किम्बरली गिल्फॉयल को पद से हटाने का फैसला किया है। गिल्फॉयल पर एक रिपब्लिकन डोनर से कथित तौर पर एक लाख डॉलर मांगने, अमेरिकी प्रशासन तक पहुंच दिलाने का वादा करने और अमेरिकी लिक्विडाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की खरीद को लेकर ग्रीस की सरकार पर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, गिल्फॉयल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को झुठा बताते हुए अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करने की बात कही है। रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार की सरकार पर दबाव बनाने के आरोपों के मुताबिक, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केटी ज़कारिया ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि प्रशासन ने गिल्फॉयल से इस्तीफा देने के लिए कहा है। इसके कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजदूत अच्छे काम कर रही थीं, लेकिन उनके बारे में सामने आई खबरें प्रशासन को पसंद नहीं आईं।

किम्बरली गिल्फॉयल ने पिछले साल सितंबर में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली थी। वह पहले डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से सगाई को लेकर भी चर्चा में रही थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, गिल्फॉयल पर अपने राजनयिक पद का इस्तेमाल ग्रीस के ऊर्जा कारोबारी एलेक्जेंड्रोस एक्सार्चू के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने बाल्कन क्षेत्र की कई सरकारों पर एक्सार्चू के एक्वोर ग्रुप

से अमेरिकी एलएनजी खरीदने का दबाव बनाया। आरोपों के मुताबिक, गिल्फॉयल ने इस कारोबारी के निजी विमान से दावोस की यात्रा भी की थी। हालांकि, इन आरोपों को लेकर उत्तरी ओर से दी गई सफाई और किसी स्वतंत्र जांच के निष्कर्षों की पुष्टि आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में ग्रीस के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान गिल्फॉयल ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिस्तोटोकिस अमेरिकी एलएनजी खरीदने से इनकार करते हैं, तो उनकी सरकार को गिराया जा सकता है। ग्रीस के ऊर्जा मंत्री स्ट्यावरोस पापास्टावरू ने बाद में इस बात से इनकार किया कि गिल्फॉयल ने उनके देश के खिलाफ कोई दबाव बनाया या धमकी दी थी। हालांकि, रिपोर्ट में किए गए अन्य दावों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। गिल्फॉयल पर रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोतोजान को पद से हटाने में भूमिका निभाने का श्रेय लेने का आरोप भी लगा। बताया गया कि रोमानिया ने अमेरिका समर्थित वर्तकल गैस कॉरिडोर परियोजना का समर्थन किया था, लेकिन अपने फेलू गैस भंडार पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त अमेरिकी एलएनजी खरीदने से इनकार कर दिया था। गिल्फॉयल से जुड़ा विवाद उस समय और बढ़ गया, जब ट्रंप के समर्थक और रिपब्लिकन डोनर एरिक डिटर्स ने अमेरिकी मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनसे वर्ष 2024 में गिल्फॉयल ने अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए 1 लाख डॉलर मांगे थे।

एक नजर

आईडीबीआई बैंक में कर्मचारियों के हित सुरक्षित: दीपम सचिव



नई दिल्ली,एजेंसी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरूणीश चावला ने कहा कि आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक पुनर्गठन को लेकर कर्मचारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। चावला ने कहा कि प्रबंधन के हस्तांतरण को लेकर सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की गई है। वित्त मंत्रालय के तहत दीपम सचिव ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन के बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा, “आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक पुनर्गठन को लेकर आज के फैसले से कर्मचारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के हस्तांतरण को लेकर सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की गई है। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2026 तक 19,108 थी। ये सौदा वित्त वर्ष 2026–27 के समाप्त होने से पहले पूरा होने की संभावना है। इसके बाद केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल से बाहर हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आईडीबीआई बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लि. की अनुपंगी मेसर्स 10955230 कनाडा इंक 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में अमूल उत्पादों का नया कियोस्क शुरु

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) ने बुधवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसर में अमूल उत्पादों का नया कियोस्क शुरु किया। संग्रहालय के ब्लॉक-एक में स्थित इस कियोस्क का उद्घाटन पीएमएमएल की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने किया। इस अवसर पर पीएमएमएल के निदेशक अश्वनी लोहानी भी मौजूद थे। पीएमएमएल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कियोस्क का उद्देश्य संग्रहालय आने वाले लोगों को जलपान और हल्के नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे खास तौर पर परिवारों और युवा आगंतुकों को सुविधा मिलेगी। कियोस्क पर अमूल के 400 से अधिक उत्पाद उपलब्ध होंगे। इनमें डेयरी उत्पाद और विभिन्न प्रकार के स्नैक्स शामिल हैं। इससे संग्रहालय परिसर में आगंतुकों को परिचित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे। पीएमएमएल के अनुसार, यह पहल प्रधानमंत्री संग्रहालय आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सुविधाजनक, सुलभ और स्वागतपूर्ण अनुभव सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है।

सुदूरवर्ती इलाकों में एकल विद्यालय जगा रहा शिक्षा का अलख : राज्यपाल

रामगढ़। एकल विद्यालय की परिकल्पना मात्र से ही यह साबित होता है कि एक बच्चे के लिए भी विद्यालय चल सकता है। ऐसे कई गांव भारत देश में हैं, जहां बच्चे कम हैं। जिसकी वजह से सरकारी स्कूल वहां नहीं खुले। लेकिन उनकी शिक्षा के लिए एकल विद्यालय ने अपना दायित्व निभाया। यह बातें रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर राजाबेड़ा गांव में एकल विद्यालय दर्शन " कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कही। उन्होंने एकल विद्यालय से जुड़े लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे लेह और लद्दाख भी गए हैं, जहां एकल विद्यालय वहां के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रही है। वैसे ही भारत देश में कई ऐसे स्थान हैं, जहां बच्चों की संख्या कम है। वहां एकल विद्यालय काम कर रहा है। खासकर भारत देश के सीमावर्ती इलाकों में जहां सरकारी विद्यालयों का संचालन नहीं हो पाता है, वहां एकल विद्यालय ही शिक्षा का अलख जगाता है। राज्यपाल संतोष गंगवार कार्यक्रम के दौरान एकल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से मिले और उनका उत्साहवर्धन किया।

दिल्ली की पहली पूर्णत : सीएनजी–चालित, ट्रक–माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन के साथ एनडीएमसी ने स्वच्छ सड़कों की दिशा में बढ़ाया एक महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली,एजेंसी। यांत्रिक स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधायक एवं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह कादियान ने आज पालिका केंद्र, नई दिल्ली से एक मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद श्री राहुल सिंह सहित परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह मैकेनिकल रोडस्वीपर मशीन विधायक निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जो शहरी स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिल्ली की पहली पूर्णतः सीएनजी-चालित, ट्रक-माउंटेड मैकेनिकल रोडस्वीपिंग मशीन है। तसमें 6 घन मीटर क्षमता वाला धूल संग्रहण हॉपर तथा सड़क की सफाई के दौरान धूल को निर्यत्रित करने के लिए जल छिड़काव प्रणाली लगी हुई है।

इस पहल का उद्देश्य आधुनिक एवं तकनीक-आधारित समाधानों को अपनाकर मैनुअल सफाई पर निर्भरता कम करना, परिचालन दक्षता बढ़ाना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में सुधार करना तथा टिकाऊ शहरी कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना है। एमआरएस मशीन में घूमने वाले साइड ब्रश तथा धूल एवं कचरे को एकत्र करने की ऑन-बोर्ड प्रणाली



लगी हुई है। यह ट्रक-माउंटेड मशीन सड़क पर मौजूद धूल, रेत, बजरी, पत्थर तथा सूखी वनस्पति को प्रभावी ढंग से एकत्र कर संग्रहण हॉपर में जमा करती है। इससे सफाई के दौरान धूल के दोबारा हवा में फैलने की समस्या कम होती है तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। एनडीएमसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक एवं आवश्यकता-

आधारित मशीनीकरण रणनीति लागू की है। इसके अंतर्गत यांत्रिक सफाई की प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित क्रम में संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत बागवानी क्षेत्रों में लीफ ब्लोअर के माध्यम से पतियों को हटाने से होती है। इसके बाद सड़कों की सफाई तथा एकत्रित बागवानी अपशिष्ट को हटाया जाता है। तत्पश्चात प्रमुख एवेन्यू सड़कों पर मैकेनिकल रोड स्वीपर (स्क्र) के माध्यम से यांत्रिक

दुर्गा पूजा 2026 : ‘ वंदे मातरम –मेरा भारत, भविष्य का भारत ’ थीम के साथ वृंदावन गार्डन दुर्गा पूजा का उद्घाटन

कोलकाता,एजेंसी। कोलकाता के वीआईपी बाजार स्थित वृंदावन गार्डन दुर्गापूजा समिति इस वर्ष अपनी पूजा के माध्यम से दर्शकों को एक अनूठी भारत यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में समिति ने ‘ वंदे मातरम –मेरा भारत, भविष्य का भारत ’ थीम का चयन किया है। प्रवेश द्वार से लेकर मां दुर्गा के दर्शन तक, पूरा मंडप भारत के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता संग्राम और भविष्य के सपनों को जीवंत करेगा। इस पूजा मंडप के उद्घाटन बुधवार शाम को हुआ है। कार्यक्रम में पूजा समिति के अध्यक्ष सोमा रानीश्री रॉय, स्वामी प्रह्लादानंद महाराज और महासचिव अधिवक्ता स्वरिक्तका भुवनेश्वरी, एमएवी राजू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

इस मंडप में दर्शकों को प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वैदिक ज्ञान और योग परंपरा की झलक देखने को मिल रही है। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ और वंदे मातरम की रचना के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया गया है, जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की लौ जलाई थी। मंडप का मुख्य आकर्षण वर्ष 2047 के बाद के उन्नत भारत की परिकल्पना और ' भविष्य की भारत माता ' का एक अनूठा रूप है। इस मातृ रूप के हाथों में भविष्य के भारत के निर्माण की मूलभूत शक्तियों के प्रतीक के रूप में अन्न, वस्त्र, शिक्षा और दीक्षा होगी। पृष्ठभूमि में भारतीय सभ्यता का प्रतीक बरगद का



पेड़ और एक शांत लेकिन शक्तिशाली शेर नजर आ रहा है। समिति का मुख्य संदेश यह है कि देश को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा। पूजा समिति की ओर से तरुण बेरा ने बताया कि दर्शन के बाद श्रद्धालु मंडप में रखे गए संकल्प वृक्ष के पास जाकर पेड़ लगाने, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने, बच्चों की शिक्षा में मदद करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने जैसे राष्ट्र निर्माण के छोटे-छोटे संकल्प ले सकेंगे। पूजा के साथ-साथ समिति ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और

सांस्कृतिक पहलों की भी योजना बनाई है। बेरा ने कहा कि हस्तशिल्प और देशी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक हजार पूर्णिमा देख चुके वरिष्ठ नागरिकों को 'सहस्र चंद्र दर्शन सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के मूक नायक के रूप में अपनी निरंतर सेवाएं देने वाले बुजुर्ग सफाई कर्मचारियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा।

68 वर्षीय विधवा मां को छोड़ने के लिए इकलौते बेटे पर पत्नी का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता: हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति पर बार-बार इस बात का दबाव बनाना कि वह अपनी 68 वर्षीय विधवा मां को छोड़कर अलग घर में रहे, मानसिक क्रूरता है। ऐसी स्थिति में पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक पाने का हकदार है। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, " अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी अपीलकर्ता की मां को उसके बेटे के साथ से वंचित करने का प्रयास प्रतिवादी की ओर से किया गया क्रूर कृत्य है। मामले में पति और पत्नी का विवाह 17 फरवरी, 2000 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनकी दो बेटियां हैं। पति अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और उत्तर प्रदेश के मैनुपुरी में अपनी 68 वर्षीय विधवा मां के साथ रहता है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी लगातार उस पर दबाव बनाती है कि वह उसे लेकर उसके मायके इटावा चला जाए। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी उसकी मां का अपमान करती थी और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है।

पति के मुताबिक, विवाह की शुरुआत से ही पत्नी की मांग है कि वह अपनी मां से अलग होकर रहे। समय के साथ यह दबाव बढ़ता गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी पुलिसकर्मी की बेटी होने का फायदा उठाते हुए उसे झूठे दहेज के मामलों में फंसाने की धमकी देती है। आरोपों के अनुसार, 6 जुलाई, 2012 को पत्नी अपने गहने और स्त्रीधन लेकर मायके चली गई। इनमें पति की मां के गहने और 50,000 रुपये नकद भी शामिल थे। वह वापस नहीं लौटी और 3 मार्च, 2015 को उसने पति के साथ रहने से अंतिम रूप से इनकार किया। इसके बाद पति ने मैनुपुरी की फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दांपत्य अधिकारों की बहाली और वैकल्पिक रूप से धारा 13 के तहत तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की। पत्नी को समन तामील नहीं हो सका, इसलिए 28 मई, 2016 को समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से वैकल्पिक तामील की प्रक्रिया अपनाई गई।

22 सितंबर, 2016 को मामले की एकतरफा सुनवाई का आदेश दिया गया। पत्नी ने न तो लिखित जवाब दाखिल किया और न ही कार्यवाही के किसी चरण में अदालत के सामने पेश हुई। 112 जुलाई, 2017 को मैनुपुरी की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने एकतरफा सुनवाई के बाद भी पति की याचिका खारिज की और उस पर खर्च भी लगाया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि पत्नी पति पर अलग रहने का दबाव डालती रही हो सकती है, लेकिन उसने गहने और नकदी ले जाने के आरोप पर विश्वास नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि किसी ने पत्नी को ये चीजें ले जाते हुए नहीं देखा और पति की मां को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया।

वाराणसी,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे और एयर शो की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के साथ ही रूट डायवर्जन की प्रभावी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त पार्किंग स्थलों की व्यवस्था, जगह-जगह दिशा सूचक साइनबोर्ड लगाने और समुचित बैरिकेडिंग कराने पर जोर दिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने तथा पर्याप्त लाइफ जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। घाटों पर मोबाइल टॉयलेट सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों और बड़े कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एयर शो जैसे बड़े आयोजन में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों, युवक मंगल दल और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए, ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। सभी पार्किंग स्थलों

परविंदर झोटा हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी : सीएम मान

चंडीगढ़,एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के पीछे किसी भी साजिश की जांच की जाएगी और इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव को मामले की गहन जांच कर हत्या से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को साजिश में संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया हुए कहा कि ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए थी। मान ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की नीति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि न केवल मनोदैहिक नशीले पदार्थों, बल्कि डॉक्टर्स की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों या अटकलों के आधार पर कोई कदम नहीं उठाने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की पूरी गंभीरता



से जांच करेगी। साथ ही, उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। परविंदर सिंह झोटा की मानसा में एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर झोटा और दुकान के मालिक के बीच विवाद हुआ था। घटना का वीडियो झोटा के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव प्रसारित हुआ था। इस दौरान उसके चार साथियों के भी गोली लगने से घायल होने की खबर है। झोटा पिछले कुछ वर्षों से मानसा और आसपास के क्षेत्रों में नशे के खिलाफ अभियान चला रहा था। वह कथित तौर पर प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामलों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाता था और संदिग्ध लोगों से सीधे सवाल भी करता था। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे और एयर शो की तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा



पर पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही घाटों की विशेष सफाई और पूरे शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नमो घाट से अस्सी घाट तक घाटों की पेंटिंग कराने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट से शहर के प्रमुख मार्गों तक विद्युत खंभों पर स्पाइरल लाइट लगाने और प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने और व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा। बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य

चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से अवगत कराया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि घाटों पर सिल्ट की सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा 300 मोबाइल टॉयलेट और 400 वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए तीन हजार सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी तथा विधायक डॉ. अवधेश सिंह, त्रिभुवन राम और सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से जुटाये 140 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। गुजरात स्थित कार्डियोवैस्कुलर मेडिकल डिवाइस निर्माता सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से पहले एंकर निवेशकों से 140 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी का ये आईपीओ गुरुवार, 15 अक्टूबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।

कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने एंकर निवेशकों को 344 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 4,071,634 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इस इश्यू के एंकर निवेश हैं हिस्सा लेने वाले कुछ प्रमुख संस्थानों में एलियांज ग्लोबल इन्वेस्टर्स फंड-एलियांज इंडिया इक्विटी, नैटिविक्स इंटरनेशनल फंड्स (लक्स) डू, लूमिस सेलेस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड और टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एयर कंडीशनर होल लाइफ एग्रेसिव ग्रोथ फंड यूलिफ शामिल हैं। सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुसार इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीमों में डीएसपी हेल्थकेयर फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड- एयर



कंडीशनर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और व्हाइटओक कैपिटल फ्लेक्सि कैप फंड आदि को शेयर आवंटित किए हैं। एंकर निवेशकों को आवंटित कुल 4,071,634 इक्विटी शेयरों में से 3,025,093 शेयर 7 स्कीमों के माध्यम से 5 घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए हैं। कंपनी ने कहा कि मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, अवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिस्कोरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड ऑफर का रजिस्ट्रार है। सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा और 19 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 327-344 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इस इश्यू के तहत मौजूदा शेयरधारक 1.38 करोड़ तक शेयर बेचेंगे। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 475 करोड़ रुपये जुटाने की है। इस आईपीओ में निवेशक न्यूनतम 43 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद 43 शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।